

राष्ट्रीय दैनिक

स्वदेश प्रेम



आर्टिकल 370 के लिए नेशनल... 06

राष्ट्रीय राजधनी दिल्ली से प्रकाशित

वर्ष-01

अंक-37

नई दिल्ली शनिवार, 25 जुलाई 2026

R.N.I NO : DELHIN/2022/86452

पृष्ठ- 8

मूल्य-01 रुपये

'वंदे मातरम' के अपमान को दंडनीय बनाने वाला विधेयक राज्यसभा में पेश



विपक्ष के हंगामे से कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 शुक्रवार को राज्यसभा में पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्ष, खासकर वामपंथी दलों ने जोरदार विरोध किया। हंगामे के चलते उपसभापति हरिवंश सिंह ने सदन की कार्यवाही 27 जुलाई (सोमवार) तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान की तरह अब 'वंदे मातरम' के अपमान या उसके गायन में बाधा

बिल में 'वंदे मातरम' के अपमान पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान, वाम दलों ने बताया असंवैधानिक

डालने पर भी अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान किया जाएगा। मौजूदा कानून में यह सजा केवल राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर लागू होती है।

विधेयक का विरोध करते हुए सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिटान ने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए नियम 67 के तहत आपत्ति दर्ज कराई। सीपीआई

के सांसद ए. रहीम और संतोष कुमार पी. ने भी विधेयक का विरोध किया। संतोष कुमार पी. ने आरोप लगाया कि सरकार छात्र आंदोलनों जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह विधेयक लाई है। उनका कहना था कि 'वंदे मातरम' देश को जोड़ने वाला गीत है, इसे राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि संविधान सभा

ने 24 जनवरी 1950 को 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानजनक दर्जा दिया था। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और उसके सम्मान को और अधिक मजबूत करना है।

विधेयक पेश होते ही विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। लगातार शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी और उपसभापति ने राज्यसभा की बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र पहले से ही विभिन्न मुद्दों, विशेषकर पेपर लीक प्रकरण को लेकर विपक्ष के विरोध के कारण बाधित रहा है। ऐसे में 'वंदे मातरम' से जुड़े इस विधेयक पर भी आगामी दिनों में संसद के भीतर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।

पेपर लीक पर सख्त कानून को कैबिनेट की मंजूरी

दोषियों को कड़ी सजा देने वाला विधेयक संसद में होगा पेश, फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी प्रावधान



क्या है कानून में नियम

- पेपर लीक करने पर: 3 से 5 साल जेल और 10 लाख तक जुर्माना
- गिरफ्तार होने पर: 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना
- एजेंसी दोषी होने पर: 1 करोड़ जुर्माना, परीक्षा की पूरी लापरवाही और अगले 4 साल परीक्षा कराने पर बैन

नई दिल्ली, एजेंसी। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है, जब देशभर में छात्र पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद में भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। सरकार

का कहना है कि नए कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर संकेत दिए थे कि सरकार पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़े दंड का प्रावधान करने वाले कानून का मसौदा तैयार कर रही है। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक से लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित होता है, इसलिए सरकार इस समस्या पर पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी।

प्रधानमंत्री ने इससे पहले पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की भी घोषणा की थी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को अगले सप्ताह

संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर, केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है।

पेपर लीक पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले- 'छात्रों को डराना-धमकाना और मारना बंद करे सरकार', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन और लाठीचार्ज किया गया, जिससे एक छात्र की आंख गंभीर रूप से घायल हो गई।

राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के लिए वह जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा,



प्रदर्शनकारियों पर कथित बर्बरता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों से माफी शामिल है। उन्होंने सरकार

से छात्रों को डराना-धमकाना और उनके साथ बल प्रयोग बंद कर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।

प्रदर्शन का असर: 16 मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद, स्कूली बच्चे परेशान



नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के चलते बृहस्पतिवार को लुटियंस दिल्ली में यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए और मोबाइल इंटरनेट सेवा भी ठप रही, जिससे आम लोगों के साथ स्कूली बच्चों और अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंडी हाउस और आसपास के इलाकों में लंबे जाम के कारण स्कूल वैन घंटों फंसी रहीं। उमस और गर्मी के बीच बच्चे भूख-प्यास से परेशान नजर आए। एक छात्र ने बताया कि वे दो घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसे रहे, जिससे काफी दिक्कत हुई। मेट्रो सेवा प्रभावित होने से विद्यार्थियों की परेशानी और बढ़ गई। कई अभिभावक बच्चों को लेने निकले, लेकिन वे भी जाम में फंस गए। वहीं, कुछ छात्र बाद में निकलने का फैसला करते हुए जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन स्थल तक भी पहुंच गए।

हिमाचल : लाहौल में टैक्सी के ऊपर गिरी चट्टान, 13 लोगों की मौत



शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर-किलाड़ सड़क मार्ग पर कड़ू नाला के पास अचानक पहाड़ी दरकने से कुल्लू से पांगी जा रही एक टाटा सुमो (एचपी-01एम-2210) मलबे में दब गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। लाहौल-स्पीति की पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला ने इसकी पुष्टि की है।

जानकारी के अनुसार, उदयपुर-किलाड़ सड़क मार्ग एक दिन पहले भूस्खलन के कारण बंद था। सड़क खुलने के बाद शुक्रवार सुबह टैक्सी पांगी के लिए रवाना हुई, लेकिन कड़ू नाला के पास अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभराकर वाहन पर गिर गया। इससे टाटा सुमो पूरी तरह मलबे में दब गई।

घटना की सूचना मिलते ही तिंदी पुलिस, जिला प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे। युद्धस्तर पर चलाए गए अभियान के दौरान एक घायल को मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जबकि अन्य

यात्रियों की तलाश की गई। बाद में प्रशासन ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि की।

मृतकों में बीर सिंह (घिसल साचा), बीर सिंह (शुण), बुद्धि सिंह, कमला कुमारी, अनिल कुमार, रेखा, सौरभ सिंह, अंजना, सोमन अमो, आरू, संजय कुमार और हंसराज शामिल हैं, जबकि एक मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उपायुक्त लाहौल-स्पीति से फोन पर बात कर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली और मौके पर पहुंचकर अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने तथा घायलों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो की मौत

- भीषण धमाके में कई घायल, दो लापता, मलबे में दबे श्रमिकों को निकालने का अभियान जारी

सहारनपुर। गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार को हुए भीषण विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दो श्रमिकों के लापता होने की भी सूचना है। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 से 25 कर्मचारी काम कर रहे थे। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की टीमों



मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। फोरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री के असुरक्षित भंडारण की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश है। प्रशासन ने घटना की जांच के साथ पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

असम बाढ़: 4 हजार से ज्यादा लोगों को बचाया

- एनडीआरएफ का राहत अभियान जारी, 59 लोगों और 48 मवेशियों का रेस्क्यू, छह शव भी बरामद

गुवाहाटी, एजेंसी। असम में लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने अब तक 4,037 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, जबकि 59 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा 48 मवेशियों का भी सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है और छह शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में नावों और विशेष उपकरणों की मदद से चौबीसों घंटे



राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। अभियान में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), जिला प्रशासन, पुलिस, आर्मेड फोर्स एवं आपातकालीन सेवाएं तथा

स्थानीय स्वयंसेवक भी सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से राहत और निकासी अभियान प्रभावी ढंग से

संचालित किया जा रहा है। उन्होंने एनडीआरएफ के जवानों की सेवा भावना और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के कई निचले इलाके अब भी जलमग्न हैं, जिससे सड़क संपर्क और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा राहत एवं बचाव दलों के साथ सहयोग करने की अपील की है। प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य भी लगातार जारी है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने दिया इस्तीफा नए राष्ट्रपति के चुनाव तक संसदीय अध्यक्ष संभालेंगे कार्यभार

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल अभी लगभग दो वर्ष शेष था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थीं। राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की है।

76 वर्षीय शहाबुद्दीन ने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताया। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे हैं और इसी वजह से पद छोड़ने का फैसला लिया है।

राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता के अनुसार, शहाबुद्दीन का इस्तीफा संसद भेज दिया गया है। इसे संसदीय अध्यक्ष हाफिजुद्दीन अहमद को सौंपा जाएगा। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार नए राष्ट्रपति के चुनाव तक संसदीय अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।

मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म पबना जिले में हुआ था। वह 1960 और 1970 के दशक में अवामी लीग के छात्र एवं युवा संगठन से जुड़े रहे और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 1975 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद सैन्य तख्तापलट का विरोध करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।

बाद में उन्होंने न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और 1996 में अवामी लीग की सत्ता में वापसी के बाद बंगबंधु हत्याकांड की जांच टीम के समन्वयक के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और अवामी लीग की सलाहकार परिषद के सदस्य बने।

दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद, यात्रियों को परेशानी -तीन स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा

नई दिल्ली (एजेंसी)। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के चलते दिल्ली में यातायात व्यवस्था प्रभावित बनी हुई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को भी 17 मेट्रो स्टेशनों को सुबह 7-30 बजे से अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। बंद रहने वाले स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवाला शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को भी मध्य दिल्ली में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही थी। कई प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग और मेट्रो स्टेशनों के बंद रहने से लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि मेट्रो सेवा प्रभावित होने के कारण उनके सफर में 40 से 45 मिनट तक अतिरिक्त समय लगा। शाम के समय दफ्तरों की छुट्टी के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। बसों में भीड़ बढ़ गई और कई लोगों को घर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से यात्रा की योजना बनाकर निकलने की अपील की है।

हजारीबाग में मुठभेड़ के बाद राहुल दुबे गिराह के दो अपराधी गिरफ्तार, एक जख्मी

हजारीबाग (एजेंसी)। हजारीबाग के केरेड़ारी थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के पुलिस और राहुल दुबे गिराह के सदस्यों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि दो अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गिराह के सदस्य चंद्रगुप्त कोल परियोजना क्षेत्र में लेवी वसूलने की फिराक में किसी बड़ी वापदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं। इसी सूचना पर केरेड़ारी थाना और पगार ओपी की संयुक्त टीम ने बुकरु गांव के पास ट्रांसपोर्टिंग मार्ग पर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने जंगल की ओर भागने का प्रयास किया और फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी। घायल अपराधी को इलाज के लिए शेष भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल और एक अवैध पिस्तौल भी बरामद की है। घटना की सूचना पर हजारीबाग एसपी अमन कुमार और बड़कागांव एसडीओपी अमित आनंद ने भी मौके का मुआयना किया। गिरफ्तार अपराधियों से राहुल दुबे गिराह के नेटवर्क और लेवी वसूली से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाई जा रही है।

असम में कई इलाके जलमग्न, बाढ़ से 7.21 लाख लोग प्रभावित, 6 लोगों की हुई मौत



गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के कई हिस्से जलमग्न हैं। अधिकारियों ने बताया कि 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इससे 7.21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। एएसडीएमए के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित जिले जिलाघाट, होइडी, कामरूप, चराइदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नागांव, कामरूप (मेट्रो), कार्बी आंगलोंग और तिनसुकिया हैं। कुल 37 राजस्व सर्कल और 883 गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि बाढ़ के कारण 25,375.44 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ का सबसे गंभीर असर शिवसागर जिले में देखा गया है, जहां 3,75,682 लोग प्रभावित हुए। इसके बाद चराइदेव में 1,86,351 और जोरहाट में 1,15,764 लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पुष्टि की कि अब तक बाढ़ के कारण 6 लोगों की मौत हुई है। शिवसागर में 4, जबकि चराइदेव जिले में दो लोग बाढ़ की चपेट में आए। बाढ़ की ताज़ा रिपोर्ट में किसी के लापता होने की सूचना नहीं है। ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 5 राजस्व सर्कल और 17 इलाके या वार्ड प्रभावित हुए हैं, जिससे 592 लोग प्रभावित हुए हैं। शहरी इलाकों में पानी भरने से कई निचले इलाकों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने प्रभावित जिलों में राहत सुविधाएं शुरू की हैं। अभी 103 राहत शिविर और 255 राहत वितरण केंद्र चल रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 24,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि 2.39 लाख से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाई गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सबसे अधिक प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं और जिला प्रशासन की टीमों राहत व बचाव अभियान में जुटी हैं।

आंदोलन का असर चुनाव की तैयारियों पर दिखा, भाजपा नेतृत्व हुआ सतर्क

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में छात्रों और विभिन्न संगठनों के आंदोलनों का असर अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी दिखाई देने लगा है। भाजपा नेतृत्व चुनाव से पहले किसी भी प्रकार के जनाक्रोश को लेकर सतर्क हो गया है। इसी रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश मंत्रियों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने तथा जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी संगठन ने जनप्रतिनिधियों से कहा है कि वे बृथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली में चल रहे आंदोलनों और विपक्ष के हमलों को देखते हुए भाजपा चुनावी माहौल को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के दौरे और जनसंपर्क अभियानों की निगरानी भी कर रहा है। वहीं विपक्ष का दावा है कि भाजपा जनता के बढ़ते असंतोष से चिंतित है, जबकि भाजपा का कहना है कि यह चुनाव पूर्व सामान्य संगठनात्मक तैयारी का हिस्सा है। आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं।

प्रदर्शन में पैलेट गन दागी, युवक का कान कटकर नीचे गिरा

मेडिकल रिपोर्टों में दर्ज हुए चोटों के निशान

नई दिल्ली (एजेंसी)। जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों की मेडिकल रिपोर्टों में ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे पैलेट गन और रबर बुलेट के इस्तेमाल की आशंका मजबूत हुई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है, जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। घायलों की मेडिको-लॉगल केस (एमएलसी) रिपोर्टों में कई गंभीर चोटों का उल्लेख किया गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जारी एक महिला प्रदर्शनकारी टोप्यो की रिपोर्ट में सॉटवैश गोली लगने से चोट दर्ज है। टोप्यो का दावा है कि उन्हें रबर बुलेट लगी थी, जिससे उनके दाहिने कान का एक हिस्सा कटकर जमीन पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि घटना के समय पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी और फायरिंग भी की जा रही थी। इसी दौरान उनके कान पर रबर बुलेट लगी और कान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सफदर्जंग



अस्पताल में भर्ती 28 वर्षीय एक पत्रकार की मेडिकल रिपोर्ट में कमर और हाथों पर पैलेट इंजरी के निशान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि जंतर-मंतर पर पैलेट गन से हमला हुआ था। घायल पत्रकार का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके शरीर में कई छेद फंसे हुए हैं, जिन्हें अधिक संख्या में होने के कारण सर्जरी के जरिए निकालना आसान नहीं है।

प्रदर्शन में घायल 19 वर्षीय साहिल का इलाज़ एम्स में चल रहा है। परिजनों के अनुसार, उनकी दाहिनी आंख में पैलेट घुस गया, जिससे आंख में गंभीर चोट आई है और एक और सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा उनके चेहरे, गर्दन, छाती और पैट में भी कई छेद फंसे हुए हैं। वहीं लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक अन्य घायल मंजूरी ने

बताया कि उनके चेहरे और गर्दन से छेदें निकालने के लिए दो सर्जरी करनी पड़ीं। उनका कहना है कि आंसू गैस का गोला फटने के बाद उन्हें चेहरे पर तेज जलन महसूस हुई और बाद में गंभीर चोटों का पता चला।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन या रबर बुलेट के इस्तेमाल से स्पष्ट इनकार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के पास दंगा नियंत्रण के उपकरण होते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल को लेकर वे कोई पुष्टि नहीं कर सकते। वहीं सीआरपीएफ ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक टिप्पणी करने से परहेज किया है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार आरएएफ के पास पैलेट गन जैसे दंगा-रोधी उपकरण उपलब्ध होते हैं और भीड़ नियंत्रण के दौरान उनका उपयोग किया जा सकता है। मेडिकल रिपोर्टों के सामने आने के बाद प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग को लेकर सवाल तेज हो गए हैं। अब इस मामले में स्वतंत्र जांच और संबंधित एजेंसियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

पीएम मोदी के वीडियो पर बोले खड़गे- पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर संसद आइए



नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट पेपर लोक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देर रात जारी किए गए वीडियो संदेश के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, तब प्रधानमंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए, न कि संसद के बाहर वीडियो संदेश जारी करना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म एक्स पर प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा कि संसद में आने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है और छात्रों के साथ हुए अन्याय पर अब तक कोई ठोस राजनीतिक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मांगों को

दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। साथ ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। खड़गे ने कहा कि इन कदमों के बाद ही शिक्षा व्यवस्था और पेपर लोक जैसे गंभीर मुद्दों पर सार्थक चर्चा संभव होगी।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात जारी वीडियो संदेश में कहा था, कि पेपर लोक रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने फाट ट्रेक कोर्ट के गठन और वैधियों को शीघ्र एवं कड़ी सजा दिलाने संबंधी मसौदा तैयार कर उन्हें सौंप दिया है। इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी और मंत्रियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

अब जगन्नाथ धाम और महाप्रसाद का त्यावसायिक उपयोग करना होगा अवैध

पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को मिले 5 नए ट्रेडमार्क

पुरी(एजेंसी)। हिंदुओं के पवित्र चार धामों में से एक, ओडिशा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने 12वें सदी के इस ऐतिहासिक मंदिर की पहचान और अनूखे परंपराओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ी कानूनी उपलब्धि हासिल की है। ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री ने जांच के दूसरे चरण के बाद मंदिर प्रशासन के पांच नए ट्रेडमार्क आवेदनों को स्वीकार कर लिया है। इन नए स्वीकृत शब्दों में जगन्नाथ धाम, श्रीक्षेत्र, महाप्रसाद, नीलचक्र और कोइली बैकुंठ शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही ट्रेड मार्क्स सदी में प्रकाशित किया जाएगा। मंदिर कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह कदम महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पवित्र संस्कृति से जुड़े धार्मिक चिह्नों और पहचान के अनधिकृत तथा व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए उठया गया है।



हाल के वर्षों में कई व्यक्तियों और निजी संस्थाओं द्वारा इन पवित्र नामों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के मामले सामने आ रहे थे। विपक्ष

विशेष भोग को महाप्रसाद कहा जाता है। नीलचक्र मंदिर के शिखर पर स्थापित अष्टधातु का सुदर्शन चक्र है और कोइली बैकुंठ मंदिर परिसर का वह पवित्र उद्यान है, जहां नव कलेवर के दौरान पुष्पों विग्रहों का समाधि-विजसन किया जाता है। अब इस सभी नामों का बिना अनुमति व्यावसायिक प्रयोग दंडनीय अपराध होगा।

मंदिर प्रशासन ने जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ी कुल 29 पहचानों और शब्दों के ट्रेडमार्क संरक्षण के लिए आवेदन किया था। इससे पहले पिछले महिने भी एसजेटीए को आनंद बाजार, पतितपावन और नीलचक्र के आधिकारिक लोगो के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण मिल चुका है। ट्रेड मार्क्स अधिनियम के तहत किए गए ये पंजीकरण पुरी मंदिर की समृद्ध विरासत, प्रामाणिकता और धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने में दृगामी भूमिका निभाएंगे।

प्रोटेस्ट के बीच सरकार के संकटमोचक कैसे बन गए नड्डा?

-वांगचुक का अनशन तुड़वाने में निगाई अहम भूमिका

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट पेपर लोक विवाद और विभिन्न संगठनों के बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों के चलते केंद्र सरकार पर जौतराफ राजनीतिक दबाव बना हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक जारी इस संग्राम के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा सरकार के प्रमुख संकटमोचक बनकर उभरे हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने से लेकर घायल छात्रों से

मुलाकात और गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में सोनम वांगचुक से दो घंटे की बातचीत तक, हर मोड़ पर उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। आंदोलन की गुरुआत से ही जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से संवाद के रास्ते खोले रखे। 20 जुलाई को जब प्रदर्शनों ख़ हुआ और प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का ऐलान किया, तब उन्होंने तुरंत बैक-चैनल संवाद सक्रिय कर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उचित मंच पर उठया जाएगा। हिंसा के

दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उन्होंने उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने का भरोसा दिया और संसद में भी स्पष्ट किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। गतिरोध को सुलझाने की दिशा में बड़ा मोड़ तब आया जब जेपी नड्डा आयी रात को मेदांत अस्पताल पहुंचे और 26 दिनों के अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इस पहल के बाद वांगचुक ने सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखीं। सरकार ने इन मांगों का सिलसिलेवार अध्ययन कर एक रूफ़ेखा तैयार की, जिसके बाद प्रधानमंत्री के आदेश और जेपी

नड्डा की सीधी मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने जेपी नड्डा ने इस संकट को टालने की दिशा में पहले बड़ी सफलता हासिल कर ली है। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शनकारियों को क्या आश्वासन मिला है, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। अब उनकी अगली बड़ी चुनौती जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों को पूरी तरह से समाप्त कराने की होगी।

बुलावा नहीं आया, तो सोशल मीडिया पर छलका दर्द-ए-दिल, भाजपा में सब कुछ ठीक है?

मुंबई (एजेंसी)। गोरखपुर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले सिक्सलेन प्लाईऑवर के लोकार्पण समारोह से एक राजनीतिक संदेश भी निकलकर सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां 995 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मंत्री डॉ. राधा मोहन



दास अग्रवाल का दर्द सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गया। उन्होंने लिखा कि घर के सामने प्लाईऑवर का उद्घाटन हुआ, जाने की इच्छा भी थी, लेकिन निमंत्रण नहीं मिला। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा में अब निमंत्रण भी राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन गया है? चार बार गोरखपुर शहर से विधायक रह चुके और वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री जैसे अहम पद पर बैठे नेता को यदि सिंच तक बुलावा नहीं मिले, तो इसे महज प्रशासनिक चूक मानना आसान नहीं होगा। डॉ. अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए जनता को बधाई भी दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुह मंत्री अमित शाह को टैग कर अपनी पीड़ा सार्वजनिक कर दी। अब राजनीतिक विश्लेषक इसे प्लाईऑवर से ज्यादा ऊंची होती सियासी दूरियां बताकर चर्चा कर रहे हैं। आखिर बुलावे की राजनीति में किसका कद बढ़ा और किसका घटा, यह सवाल फिलहाल गोरखपुर की सियासत में सबसे ज्यादा गुंज रहा है।

राहुल ने पीएम मोदी पर कसा तंज बोले- पहले शिक्षा मंत्री को हटाइए

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लोक विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आधी रात को वीडियो जारी कर प्रदर्शनकारी छात्रों की समझदारी का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटया जाए, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को सजा दी जाए और सरकार इस पूरे मामले पर देश के छात्रों से माफी मागे।

राहुल गांधी का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बैकनेट की बैठक में पेपर लोक के खिलाफ और अधिक सख्त कदम उठाने पर



चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार की

जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता अभिजीत दिक्के ने लड़ाख के

26 जुलाई को पूरे देश में सपा मनाएगी संविधान-मानस्तंभ स्थापना दिवस

-अखिलेश बोले- जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा, संविधान ही है ढाल

लखनऊ (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 26 जुलाई को पूरे यूपी और देशभर में संविधान-मानस्तंभ स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इसी दिन कोलहापुर के तत्कालीन शासक राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज ने महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा से प्रेरित होकर आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। उनके मुताबिक यह सामाजिक न्याय को व्यवहार में लाने की एक ऐतिहासिक पहल थी, जिसने आगे चक्कर संविधान में समाजा और

सामाजिक न्याय के प्रावधानों की मजबूत नींव रखी।

सपा प्रमुख ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा

कि आरक्षण दिवस 26 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने संविधान-मानस्तंभ स्थापना दिवस के रूप में से भी मनाने का फैसला लिया है क्योंकि इसी दिन महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सकल्पित 'आरक्षण' को कोलहापुर के परम आदरणीय-अनुकरणीय श्रीमंत महाराज राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज ने महात्मा ज्योतिबा फुले के अपने कोलहापुर राज्य में लागू किया था। इसी दिन आरक्षण देने का शुभारंभ हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक न्याय की भावना को आरक्षण के रूप में इसी दिन अमल में लाया गया था, जो

आगे चलकर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के सद्गुणियों से हमारे संविधान में एक जनधिकार के रूप में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का की स्थापना का मूल सिद्धांत भी। इसके लिए हर वर्ष 26 जुलाई से अधिक ऐतिहासिक अवसर और क्या हो सकता है, क्योंकि विचार को सही में लागू करना ही तो सबसे बड़ा और प्रभावशाली उदाहरण होता है, जो परम

आदरणीय-अनुकरणीय श्रीमंत महाराज राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज जी ने इस दिन लागू करके दिखाया था।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष भी 26 जुलाई को पूरे उत्तर

प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी संविधान-मानस्तंभ स्थापना दिवस का आयोजन कर रही है। इस दिन सपा के मुख्यालय व सभी कार्यालयों में एक सादगीपूर्ण समारोह में भारत के संविधान की प्रतिक के सानिध्य में संविधान-मानस्तंभ स्थापना दिवस आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके पीछे मूल भावना यही है कि संविधान-मानस्तंभ वस्तुतः पीड़ी-प्रकाशास्तंभ के रूप में हमारे सामाजिक न्याय के राज' की स्थापना के संकल्प का मार्ग सदैव प्रकाशित और प्रशस्त करता रहे। जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। संविधान ही ढाल है, संविधान ही कवच है। संविधान ही गैर बराबरी दूर करके समता-समानता को सुनिश्चित करेगा और हमारे 'बंधु राष्ट्र' बनाने के महा-संकल्प को भी।

भारत ने पीएम रहमान को बिक्स सम्मेलन का भेजा न्योता

-बांग्लादेश से संबंधों को पटरी पर लाने की पहल

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत और पड़ोसी मुल्क के बीच उपजे कूटनीतिक तनाव के बीच भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। भारत ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें बिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण भेजा है। बांग्लादेश के बिक्स का सदस्य देश न होने के बावजूद ढाका को आमंत्रित करना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को पुनः पटरी पर लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने पुष्टि की है कि भारतीय पक्ष से प्राप्त निमंत्रण विदेश मंत्रालय को मिल चुका है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले फरवरी में भी तारिक रहमान को भारत यात्रा का न्योता दिया था। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने के कारण बांग्लादेश को घेरलू



राजनीति में किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के डर से रहमान अब तक भारत यात्रा को लेकर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। पद संभालने के बाद वह अपनी पहली विदेश यात्रा पर परंपरा से हटकर भारत के बजाय चीन गए थे। बांग्लादेश लंबे समय से बिक्स समूह का सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा रखता है और इस दिशा में उसे चीन व रूस का समर्थन भी प्राप्त है। ऐसे में नई दिल्ली में होने वाला यह शिखर सम्मेलन ढाका के लिए कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद खास माना जा रहा है। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी शामिल होने की संभावना है। इससे पहले 2016 में भी जब भारत ने बिक्स की

मेजबानी की थी, तब बांग्लादेश को बिम्स्टेक सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। हाल ही में मनीला में आसियान फोरम के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के बीच भी सख्त मुलाकात हुई थी। भारत की इस वर्ष की बिक्स अध्यक्षता ब्रिटिश फॉर रेंजिलएस, इनेवेशन, कोऑरेशन एंड स्टर्नेनैबिलिटी विषय पर केंद्रित है। इस बढ़ते मंच पर बांग्लादेश की भागीदारी से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक संबंधों को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।



एनीमिया मुक्त भारत अभियान में जिला ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान

डीसीसीएम की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगराधीश सिमरन ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए निर्देश



संवाददाता सोनीपत। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जिला समन्वय एवं समन्वयन समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन शुक्रवार को जिला सचिवालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता सिटी मजिस्ट्रेट ने की जबकि सिविल सर्जन डॉ. अनुराधा जैन ने सह-अध्यक्षता की। बैठक के संयोजक डॉ. जितेन्द्र सिंह, जिला नोडल अधिकारी, एनीमिया मुक्त भारत रहे। बैठक के दौरान डॉ. जितेन्द्र सिंह ने एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की विस्तृत प्रस्तुत करते हुए बताया कि एक माह तक चले विशेष अभियान के दौरान जिला में छह लक्षित

लाभार्थी वर्गों के अंतर्गत 66,347 लाभार्थियों की हीमोग्लोबिन जांच (स्क्रीनिंग) की गई तथा 2,514 एनीमिक लाभार्थियों का सफल फॉलो-अप किया गया। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर जिला ने पूरे हरियाणा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जिले में छहों लक्षित श्रेणियों में एनीमिया की व्यापकता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए बताया कि भविष्य में किन वर्गों एवं क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि एनीमिया की दर में प्रभावी कमी लाई जा सके। प्रस्तुति के दौरान आयुष्यसंकेट टीम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़खालसा तथा सीएचसी जुआं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की विशेष

सराहना की गई। इन केंद्रों ने स्क्रीनिंग एवं रिपोर्टिंग में उल्लेखनीय कार्य किया। वहीं सीएचसी खरखोदा एवं सीएचसी हलालपुर की स्क्रीनिंग प्रगति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को माइक्रो प्लान तैयार कर स्क्रीनिंग गतिविधियों में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अभियान में सहयोग के लिए ममता एनजीओ का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा जिले के चार गांवों में समुदाय आधारित गतिविधियों एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अभियान को मजबूत सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग एवं साझेदारी की आशा व्यक्त की। बैठक में हंस फाउंडेशन द्वारा कुंडली ब्लॉक में संचालित गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। क्षेत्रीय समन्वयक राहुल चौहान ने जिले में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर अपना फीडबैक साझा करते हुए कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट, सोनीपत ने कहा कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों, विकास सहयोगी संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा।



उन्होंने प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक स्क्रीनिंग, उपचार, आयरन-फोलिक एसिड की उपलब्धता तथा जन-जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन डॉ. अनुराधा जैन ने कहा कि नियमित हीमोग्लोबिन जांच, समय पर उपचार, गुणवत्तापूर्ण परामर्श तथा शत-प्रतिशत रिपोर्टिंग के माध्यम से जिले में एनीमिया की व्यापकता को परेशानी से कम किया जा सकता है। उन्होंने सभी विभागों से अभियान को जन-आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया। बैठक के अंत में सभी विभागों एवं विकास सहयोगी संस्थाओं ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान को और अधिक प्रभावी

बनाने तथा जिले में एनीमिया की दर में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए समन्वित प्रयास निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। इस दौरान शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आरबीएसके तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें उप जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत, बीईओ सोनीपत, बीईओ गनौर, सीडीपीओ, स्वास्थ्य विभाग के सभी उप सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, सभी वरिष्ठ नर्सिकला अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक हरीश कौशिक, डीएसी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त डायरी

फोन पर बात करने पर प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या: फरीदाबाद में गुस्सा पति ने चुन्नी से गला घोंटा



फरीदाबाद (एजेंसी)। हरियाणा के फरीदाबाद में 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। महिला की हत्या उसके ही पति ने चुन्नी से गला घोंटकर की थी। वारदात के बाद आरोपी ने घर से सोने के गहने गायब कर चोरी का नाटक रचा, ताकि हत्या को लुपटात की घटना दिखाया जा सके। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर कोर्ट से 6 दिन के रिमांड पर लिया है। जांच में सामने आया कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। 22 जुलाई को पत्नी को किसी से मोबाइल पर बात करते देख वह भड़क गया। दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के मीठापुर निवासी नमिता (22) की शादी नवंबर 2025 में ग्रीन फील्ड कॉलोनी निवासी रंजीत से हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी। नमिता ग्रेजुएट थी और शादी के बाद आठ महीने की गर्भवती थी। 22 जुलाई को नमिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नमिता के पिता शिवनारायण कामत ने बताया था कि 22 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे नमिता की ससुराल से कॉल आई। उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। इसके आधे घंटे बाद दोबारा कॉल आई। देवर ने कहा कि नमिता बेहोशी की हालत में पड़ी थी। जब उसे उठाने की कोशिश की, तो उसने कोई हलचल नहीं की। इसके बाद उसे सेक्टर-31 के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने नमिता को मृत घोषित कर दिया। शिवनारायण ने बताया कि अस्पताल की जांच में बेटी के रगले पर रस्सी से गला दबाने जैसे निशान मिले। शादी के कुछ समय बाद उनकी बेटी को पता चला था कि उसका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है। नमिता अक्सर उसे दूसरी महिला से बात करने के लिए टोकती थी। रंजीत कई बार मारपीट कर चुका था। ग्रीन फील्ड चौकी पुलिस ने रंजीत चौधरी, ससुर विजय कांत चौधरी, सास बुच्चि चौधरी, देवर चरणजीत चौधरी और संजीत चौधरी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच क्राइम ब्रांच NIT को सौंपी गई। पूछताछ के दौरान रंजीत ने हत्या की बात कबूल कर ली।

पानीपत में बंद कमरे में मिला युवक का शव: 5 दिन से पड़ा था, 3 महीने पहले किराए पर रहने आया

संवाददाता पानीपत। शहर के खट्की मोहल्ला में एक बंद कमरे से युवक का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 5 दिन से कमरे में बंद पड़े शव का पता तब चला, जब आसपास के लोगों को तेज दुर्गंध आने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस



और जन सेवा दल की टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कमरे की ओर से तेज बदबू आ रही थी। जब दुर्गंध लगातार बढ़ने लगी तो लोगों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जन सेवा दल की टीम को भी बुलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर फोल्डिंग पर एक युवक मृत अवस्था में पड़ा मिला। शव काफी हद तक गल-सड़ चुका था और कमरे में मक्खियां भिन्नभिन्न रही थीं। पुलिस और जन सेवा दल ने सावधानीपूर्वक शव को कमरे से बाहर निकालकर कब्जे में लिया। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि मृतक करीब तीन महीने पहले ही किराए पर रहने आया था। वह पेशे से टाइल मिस्त्री था। वहीं मकान मालिक के पास भी उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। पुलिस को मौके से मृतक का कोई पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं मिला। हालांकि उसका मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस उसके परिजनों और पहचान का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान और मौत के कारणों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकता है।

तेजाब से हमला कर हत्या करने वाले को उम्रकैद: हिसार कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुमाना



संवाददाता हिसार। सेशन कोर्ट ने तेजाब से हमला कर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सेशन जज अलका मलिक की कोर्ट ने ऋषि नगर निवासी संजय पर एक लाख रुपए का जुमाना भी लगाया। यह मामला 12 जून 2022 को सिटी थाना पुलिस ने दर्ज किया था। न्यू ऋषि नगर निवासी अश्वनी ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह टैक्सि चलाता था। उसकी पत्नी की करीब 12 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और उसकी दो बेटियां हैं। अश्वनी के अनुसार, घटना से लगभग एक सप्ताह पहले वह शाम करीब साढ़े पांच बजे अग्रसेन भवन के पास बैठा था। उस समय उसके साथ महावीर कॉलोनी निवासी सीटू और नगर पालिका कर्मचारी राज भी मौजूद थे। इसी दौरान ऋषि नगर निवासी संजय वहां पहुंचा और अपने साथ लाई तेजाब की बोतल खोलकर उसके पजामे के अंदर जांच पर तेजाब डाल दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया। तेजाब से गंभीर रूप से झुलसने के बाद राहगीरों ने अश्वनी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। अश्वनी ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया था कि संजय ने बिना किसी वजह उस पर तेजाब डालकर उसे जलाया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलाज के दौरान अश्वनी की मौत हो गई। इसके बाद सिटी थाना पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू की और आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में कोर्ट में चालान पेश किया था। सरकारी अधिका सुनील पारुथी ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था। शुक्रवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

दहेज प्रथा उन्मूलन पर जागरूकता कार्यक्रम



संवाददाता सोनीपत। जिले के गोहाना क्षेत्र के गांव गढ़ी उजाले खां में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दहेज प्रथा उन्मूलन और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) सुशीला देवी ने की। कार्यक्रम में सकल सुपरवाइजर इंद्रावती के साथ-साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मीना, मंजू और सुमन भी उपस्थित रहीं। उपस्थित ग्रामीण महिलाओं और अन्य लोगों को दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि दहेज लेना और देना कानूनी अपराध होने के साथ-साथ एक गंभीर सामाजिक बुराई भी है। कार्यक्रम में सभी से आह्वान किया गया कि विवाह को लेन-देन का माध्यम न बनाएं और दहेज मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहयोग दें। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के उद्देश्यों पर भी प्रकाश

डाला गया। उपस्थित लोगों को बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त, बाल विवाह रोकने संबंधी जानकारी भी दी गई। बताया गया कि लड़कियों का विवाह 18 वर्ष और लड़कों का विवाह 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही किया जाना चाहिए। सीडीपीओ सुशीला देवी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में बेटियों को समान अवसर प्रदान करना और दहेज जैसी कुप्रथा का पूरी तरह बहिष्कार करना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। सकल सुपरवाइजर इंद्रावती ने उपस्थित महिलाओं से अपने परिवार और समाज में दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देने तथा बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने दहेज प्रथा का विरोध करने, बाल विवाह पर रोक लगाने और बेटियों की शिक्षा व सम्मान को बढ़ावा देने का सामूहिक संकल्प लिया।

बरसात के लिए सोनीपत डीसी की अधिकारियों संग मीटिंग

सभी सड़कों के गड्डे तुरंत भरने के लिए निर्देश, बोली-लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी



संवाददाता सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने मानसून की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों को पूरी सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जनसुविधाओं में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। शुक्रवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उपायुक्त नेहा सिंह ने बरसाती सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम विंडो, समाधान शिविर, महारी सड़क पोर्टल और ई-ऑफिस प्रणाली जैसे जनहित से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जलभराव वाले स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाए। इन स्थानों से पानी की त्वरित निकासी के लिए अलग से कार्य योजना तैयार की जाए। उपायुक्त ने कहा कि मानसून के दौरान प्रशासन की प्राथमिकता

लोगों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नेहा सिंह ने जोर दिया कि जलभराव की समस्या केवल आवागमन को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि जनजीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी संबंधित विभाग मिलकर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने हॉटस्पॉट स्थानों पर पॉपिंग सेट, सिमरन और कर्मचारियों की तैनाती के भी निर्देश दिए, ताकि बारिश के दौरान तत्काल कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली की लाइनों से संपर्क में आने वाले पेड़ों की शाखाओं को हटाने, इसलिए सड़क मरम्मत कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने महारी सड़क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों



विद्युत आपूर्ति बाधित होती है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए छंटाई के बाद पेड़ों की टहनियों को तुरंत मौके से उठाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि सड़कों पर आवागमन प्रभावित न हो और आमजन की किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम तथा संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि जिले की सभी प्रमुख एवं आंतरिक सड़कों का निरीक्षण कर सभी गड्डों की प्राथमिकता के आधार पर भरवाया जाए, ताकि बरसात के समय लोगों को वहां से आने जाने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सड़क मरम्मत कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने महारी सड़क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों

की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके पश्चात उन्होंने समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार को परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम तथा संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि जिले की सभी प्रमुख एवं आंतरिक सड़कों का निरीक्षण कर सभी गड्डों की प्राथमिकता के आधार पर भरवाया जाए, ताकि बरसात के समय लोगों को वहां से आने जाने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सड़क मरम्मत कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने महारी सड़क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों

भारत विकास परिषद द्वारा वीर रस काव्य पाठ प्रतियोगिता का सफल आयोजन 14 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने दिखाई ओजस्वी प्रतिभा



संवाददाता सोनीपत। भारत विकास परिषद, सोनीपत द्वारा शुक्रवार को ऋषिकुल विद्या पीठ, सोनीपत में वीर रस काव्य पाठ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों एवं आत्मविश्वास का विकास करना तथा ओजस्वी काव्य के माध्यम से देशभक्ति की भावना

को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता में शहर के लगभग 14 प्रतिष्ठित विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री एस.के. शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि श्री धीरज शर्मा द्वारा अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन कर किया

गया। प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में जानकीदास कपूर पब्लिक स्कूल की समारिथा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऋषिकुल वर्ल्ड अकादमी की कामाक्षी द्वितीय तथा शिवा शिक्षा सदन की नीलाक्षी तृतीय स्थान पर रहीं। सीनियर वर्ग में ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिविन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल की तनिखा ने द्वितीय तथा

शिवा शिक्षा सदन की जिज्ञासा ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन इंदु बाला, श्री वरेंद्र एवं श्रीमती सुषमा दुडेजा ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से किया। निर्णायकों ने प्रतिभागियों की प्रस्तुति, उच्चारण, भावाभिव्यक्ति, मंच संचालन क्षमता एवं काव्य प्रस्तुति के प्रभाव को आधार बनाकर विजेताओं का चयन किया। कार्यक्रम का प्रभावशाली मंच संचालन शारदा रहलान ने किया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद, सोनीपत के अध्यक्ष संजीव सरदाना,

सचिव रंजना कुकरेजा, नीरज शर्मा, अरुण बंसल, दीपक शर्मा, शारदा रहलान, मंजू गर्ग, अर्चना

गीता, संजय अरोड़ा तथा ऋषिकुल विद्या पीठ के प्रधानाचार्य उमेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं शिक्षाविद् उपस्थित रहे। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि

वीर रस काव्य भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, साहस, आत्मविश्वास तथा प्रभावशाली अभिव्यक्ति कौशल का विकास करते हैं। भारत विकास परिषद भविष्य में भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु इस प्रकार की साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन निरंतर करती रहेगी। कार्यक्रम का समापन सभी विजेताओं एवं प्रतिभागियों को बधाई देते हुए तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हुआ।

संक्षिप्त समाचार

मानसिक तनाव में था अतुल, मां से कहा था दामिनी मुझे मरवा देगी

मेरठ, एजेंसी। चर्चित अतुल हत्याकांड की जांच में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। संकेत मिल रहा है कि अतुल लंबे समय से मानसिक तनाव में था। उसने अपनी निजी परेशानियां परिवार या करीबी लोगों से साझा नहीं की थीं। अतुल ने परिवार की मर्जी के खिलाफ दामिनी से प्रेम विवाह किया था। इसी कारण वह वैवाहिक जीवन की दिक्कतें किसी को बता नहीं पा रहा था। अतुल को पत्नी दामिनी और उसके प्रेमी तुषार की नजदीकियों पर शक था। उसने दामिनी से इस बारे में सवाल भी किया था। दामिनी ने किसी भी संबंध से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी अतुल का संदेह दूर नहीं हुआ। वह भीतर-ही-भीतर घुटता रहा। अतुल ने कुछ समय पहले अपनी मां से जान को खतरा बताया था। उसने आशंका जताई थी कि दामिनी उसे मरवा सकती है। हालांकि, उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। दामिनी पहले भी अतुल को खाने में नशीली गोлияं देती थीं। पुलिस अब इस पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। वह यह जांच रही है कि क्या दामिनी को दवा की सही मात्रा का अभ्यास था। पुलिस सभी साक्ष्यों को जोड़कर इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है

आरोपी पारस सोम की उम्र पर फैसला टला, पत्रावली आरक्षित

मेरठ, एजेंसी। कपसाइड हत्याकांड के मुख्य आरोपी पारस सोम की उम्र को लेकर बुधवार को निर्णय पारित नहीं हो पाया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने समय के अभाव के चलते पत्रावली को निर्णय हेतु आरक्षित कर लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर फैसला आने की उम्मीद है। आरोपी पारस सोम को जुवेनाइल बोर्ड ने पहले बालिग घोषित किया था। इस फैसले के विरुद्ध न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत में चुनौती दी गई थी। अदालत में यह याचिका दायर की गई थी कि आरोपी को नाबालिग माना जाए। बुधवार को इस महत्वपूर्ण प्रकरण में फैसला आने की उम्मीद थी। हालांकि, समय की कमी के कारण अदालत निर्णय नहीं सुना सकी। अब पत्रावली को निर्णय के लिए नियत किया गया है। अगली सुनवाई पर इस मामले में अंतिम फैसला आने की संभावना है। यहां मामला सरचना थाना क्षेत्र के कपसाइड गांव से जुड़ा है। आरोपी पारस सोम पर 08 जनवरी 2026 को अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या करने उसकी बेटी रूबी का अपहरण करने का भी आरोप है। इस संबंध में थाना सरचना में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की उम्र का निर्धारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शादी में आए युवक ने पेड़ पर फंदा लगाकर दी जान

आगरा, एजेंसी। थाना लोधा क्षेत्र में गांव बाढ़ीन में एक शादी समारोह में आए युवक ने पत्नी से विवाद के बाद पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। बुधवार सुबह उसका शव पेड़ से लटकता मिला। गौतमबुद्ध नगर के थाना जेवर के गांव रायपुर गांव निवासी पवन कुमार (25) पुत्र गोपाल अपनी पत्नी नीरा के साथ मंगलवार को गांव बाढ़ीन में आया था। यहां उसकी पत्नी के मामा रामचरण के बेटे पुष्पेड़ की बुधवार को बरात जानी थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। मंगलवार रात किसी बात को लेकर पवन और उसकी पत्नी नीरा के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पवन घर से निकल गया। बुधवार सुबह भरतपुर की मढ़ी के पास एक नीम के पेड़ पर उसका शव उसकी ही शर्ट के फंदे से लटका मिला। खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सीओ मथाना महेश कुमार ने बताया मामले में परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है।

खैराती टोला छोड़कर बाकी जगह मिलेगा पानी, सीवर लाइन का काम जारी

आगरा, एजेंसी। आगरा में नमामि गंगे के तहत खैराती टोला पंपिंग स्टेशन पर सीवर की लाइन से क्रॉस कर रही पानी की लाइन हटाने के काम के कारण जलनिगम ने दो दिन का शटडाउन लिया था, लेकिन कैप का उपयोग करने के कारण बृहस्पतिवार को खैराती टोला छोड़कर अन्य जगहों पर जलापूर्ति सामान्य रहने का दावा किया गया है। बुधवार रात ही लाइन को चालू किया गया, लेकिन ताजगंज, खैराती टोला लाइन की जगह अन्य जगहों पर आपूर्ति की गई। जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि दो दिन का शटडाउन जलनिगम ने लिया था लेकिन सीवर लाइन क्रॉस करने के काम में पानी की लाइन में कैप का उपयोग किया गया। अब जब वह लाइन जोड़ेंगे, तब पानी की आपूर्ति बंद की जाएगी हालांकि पानी की लाइन को पाटने पर गड्डे में पानी भर गया। दरआसल, पाइपलाइन में इतना पानी रहता है कि गहरे गड्डे को पूरा भर दे। डी-वाटरिंग के बाद दोपहर में काम शुरू किया गया। पानी भरने से कर्मचारी गहरे गड्डे में काम नहीं कर पाए। जलकल महाप्रबंधक के मुताबिक बृहस्पतिवार को जलापूर्ति सामान्य रहेगी।

मुड़िया मेला पर आगरा और मथुरा के बीच चलेंगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेन

आगरा, एजेंसी। मुड़िया पूर्णिमा और गोवर्धन परिक्रमा मेले में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आगरा मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए विशेष व्यवस्था की है। 24 से 31 जुलाई तक आगरा कैट-मथुरा के बीच तीन जोड़ी मेमू स्पेशल चलाई जाएंगी।

जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि झांसी-आगरा कैट पैसेंजर का विस्तार डीग तक और नई दिल्ली-आगरा कैट इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार ग्वालियर तक किया गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत की चार एक्सप्रेस ट्रेनों को मथुरा और आगरा कैट पर दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है।

ट्रेन संख्या 11901-11902 झांसी-आगरा कैट अब 29-30 जुलाई को डीग तक जाएगी। वापसी में 30 व 31 जुलाई को डीग से झांसी चलेगी। ट्रेन 14212-14211 नई दिल्ली-आगरा कैट इंटरसिटी 24 से 31 जुलाई तक ग्वालियर तक और वापसी में 25 जुलाई से 1 अगस्त तक ग्वालियर से



संचालित होगी।

आगरा कैट से मथुरा के बीच तीन जोड़ी मेमू स्पेशल सुबह 10:35, 11:15 और 11:30 बजे रवाना होकर 12:15, 12:45 और 1:10 बजे मथुरा पहुंचेंगी। वापसी में मथुरा से 12:45, 2:05 और 2:30 बजे चलकर आगरा कैट 2:40, 4:10 और 4:15 बजे पहुंचेंगी। साथ ही 12652,

12708, 12642 और 12650 एक्सप्रेस को मथुरा और आगरा कैट पर अस्थायी ठहराव दिया गया है।

कोलकाता इंटरसिटी दो दिन निरस्त अजमेर-सियालदह का बदला रूट : पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल के मुगमा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के चलते सितंबर में आगरा होकर गुजरने वाली

नागर शैली में बनेगा काशी का जगन्नाथ मंदिर, 151 फीट होगी ऊंचाई

वाराणसी, एजेंसी। पुरी के जगन्नाथ धाम की तर्ज पर काशी में जगन्नाथ मंदिर का पुनर्विकास किया जाएगा। मुख्य शिखर की ऊंचाई 151 फीट प्रस्तावित है। इसके तहत करीब एक लाख वर्गफीट क्षेत्र में जगन्नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके लिए बुधवार को इंजीनियरों और ग्राफिक्स डिजाइनरों की टीम ने मंदिर पहुंचकर नाप-जोख की। वहीं, राजस्थान से आए शिल्पकारों की टीम ने भी मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। जगन्नाथ मंदिर का स्वरूप इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि मां गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालु नदी तट से ही मंदिर के मुख्य शिखर के दर्शन कर सकेंगे।

परिसर में पारंपरिक ज्ञान और वेदार्थयन की व्यवस्था भी होगी। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क महाप्रसाद और भोजन की व्यवस्था रहेगी। साथ ही अत्यंत कम शुल्क पर उठरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। निरीक्षण करने वाली टीम में हेड इंजीनियर रजनीकांत उपाध्याय, आर्किटेक्ट अमित कुमार गुप्ता, आर्किटेक्ट जयेश तिवारी, ग्राफिक्स डिजाइनर संजेश मिश्रा, अभिषेक पांडेय और मानसिंह पटेल शामिल रहे। टीम ने निर्माण कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की। सबसे पहले परिसर में स्थित गुरुड़ मंदिर की नाप-जोख की गई।



ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी के सचिव शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर की मूल संरचना और प्राचीन विग्रहों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐतिहासिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए निर्माण कार्य कराया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने में करीब 41 महीने लगने का अनुमान है। यदि कार्य तय समय पर पूरा हुआ तो दिसंबर 2029 तक मंदिर नए स्वरूप में नजर आएगा।

पहले चरण में निर्माण पर करीब 30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की नागर शैली में किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान के शिल्पकार गिरिराज सैनी और उनकी टीम को सौंपी गई है। उनका टीम में कारीगर विष्णु योगी और अशोक योगी शामिल हैं। धौलपुर (राजस्थान) से लाए गए लाल, गुलाबी और सफेद पत्थरों से मंदिर की नक्काशी और निर्माण कार्य किया जाएगा।

नेपाल सीमा पर आबकारी-एसएसबी का संयुक्त प्रहार: 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, तस्करों के नेटवर्क पर बड़ी चोट



स्वदेश प्रेम, रमजान अली बलरामपुर, 24 जुलाई 2026। नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने एक बार फिर प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार, उप आबकारी आयुक्त देवीपाटन प्रभार (गोंडा) के पंचवेक्षण तथा जिला आबकारी

अधिकारी बलरामपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत शुक्रवार को नेपाल सीमा के समीप संयुक्त छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग सर्किल-1 सदर की टीम ने थाना हरैया क्षेत्र के मढ़ीपुर चौधरीडीह अंतर्गत महादेव बाकी में 9वीं वाहिनी एसएसबी (9 इठ रड) के साथ संयुक्त दबिश दी।



अभियान के दौरान अवैध शराब बरामद होने पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दो अभियोग दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी मुलूंजय प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान लगाया जा रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि अवैध

शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दे, ताकि दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस संयुक्त अभियान में आबकारी निरीक्षक सर्किल-1 रामधनी वमां, प्रधान आबकारी सिपाही उमेश कुमार, 9वीं वाहिनी एसएसबी के जवान तथा आबकारी विभाग की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई।

चार ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इसमें आगरा कैट-कोलकाता इंटरसिटी एक्सप्रेस अप और डाउन में निरस्त रहेगी, जबकि सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस और अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस चार दिनों तक बदले मार्ग से चलेंगी।

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 13167 कोलकाता-आगरा कैट एक्सप्रेस 24 सितंबर तथा 13168 आगरा कैट-कोलकाता एक्सप्रेस 26 सितंबर को निरस्त रहेगी। वहीं 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस 23 से 26 सितंबर तक सीतारामपुर-धनबाद-गया-पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बजाय सीतारामपुर-झाझा-पटना-पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मार्ग से चलेगी। इसी प्रकार 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस भी 23 से 26 सितंबर तक पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-गया-धनबाद-सीतारामपुर के स्थान पर पटना-झाझा होकर संचालित होगी।

आबूलेन पर घड़ी कारोबारी की दुकान पर पहुंचा युवक, बढ़ो के नाम से मांगी एक करोड़ रंगदारी, भीड़ ने धुना

मेरठ, एजेंसी। आबूलेन पर बुधवार को घड़ी कारोबारी नितेश अग्रवाल के दुकान पर एक करोड़ की रकम नहीं मिली तो अंजाम सही नहीं होगा। साथ ही रंगदारी मांगने वाले युवक ने पांच लाख के इनामी कुख्यात बदमाश बदन सिंह बड़ो का नाम लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रारंभिकी दर्ज कर ली है। मौके से आरोपी महलवाला किठौर निवासी रोहित त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

सिविल लाईंस के मोहनपुरी विकासपुरी निवासी नितेश अग्रवाल और नीरज अग्रवाल की आबूलेन पर घड़ी की दुकान है। साथ में फाइनैस का भी बड़ा काम है।



बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बाइक पर सवार होकर एक युवक नितेश अग्रवाल की दुकान पर पहुंचा। उसने नितेश अग्रवाल से कहा कि एक करोड़ रुपये का इंतजाम कर लो। बदन सिंह बड़ो को यह रकम भेजनी है, समय और दिन बता दिया जाएगा।

कारोबारी ने डायल 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को मौके पर बुला लिया। तब तक आसपास के दुकानदारों ने मिलकर आरोपी

मंडी परिसर में ही निपटाना होगा

गीला-सूखा कचरा, नोटिस जारी

बरेली, एजेंसी। शहर की फल एवं सब्जी मंडी में अब कचरा बाहर फेंकने की व्यवस्था समाप्त होगी। नगर निगम ने मंडी से निकलने वाले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु सख्त रुख अपनाया है। मंडी परिषद को नोटिस जारी कर परिसर में ही गोले और सूखे कचरे का निस्तारण अनिवार्य किया गया है।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि फल और सब्जी मंडी से रोज बड़ी मात्रा में जैविक अवशेष उत्पन्न होते हैं। इनके उचित निस्तारण न होने से तीखी दुर्गंध, गंदगी और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए कचरे का प्रबंधन उसके स्रोत पर ही सुनिश्चित होगा। निगम के नोटिस में सुप्रिम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) तथा केंद्र व राज्य सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन दिशा-निर्देशों का हवाला है। इनके तहत बड़े संस्थानों के लिए कचरे का पृथक्करण और निस्तारण अनिवार्य है।

नगर निगम ने मंडी परिषद को जैविक कचरे से खाद बनाने हेतु परिसर में ही खाद संयंत्र लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे कचरे का प्रभावी निस्तारण होगा और तैयार जैविक खाद का व्यावसायिक उपयोग भी संभव होगा। मंडी से निकलने वाले कचरे को अब बाहर नहीं फेंका जा सकेगा। गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण और निस्तारण मंडी परिसर के भीतर ही करना होगा। जैविक कचरे से खाद बनाने के लिए खाद संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण नियमों के अनुसार, अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को गीले कचरे का निस्तारण परिसर के भीतर ही करना अनिवार्य है। एनजीटी और शासन के दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कचरे के परिवहन पर निर्भरता घटाना है।

लहरतारा में रोजेंन ई-बाइक शोरूम का भव्य उद्घाटन,महापौर अशोक तिवारी ने फीता काटकर किया शुभारंभ



(संतोष कुमार सिंह)

वाराणसी:- लहरतारा क्षेत्र में रोजेंन ई- बाइक के नए शोरूम का भव्य उद्घाटन समारोह 24 जुलाई शुक्रवार को उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी ने फीता काटकर एवं दीप

प्रज्वलित कर शोरूम का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकता हैं और इनके उपयोग को बढ़ावा देना समय की मांग है कार्यक्रम में कैट विधायक सौरव श्रीवास्तव विशिष्ट



अतिथि के रूप में उपस्थित रहे उन्होंने रोजेंन ई-बाइक परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता चलन स्वच्छ और हरित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

समारोह में कांता देवी, नीलिमा पम्मनानी,

ज्ञानचंद पम्मनानी, भावेश पम्मनानी, जय प्रकाश मननी, रेशमा मननी एवं कमला प्रसाद सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे सभी अतिथियों ने नए शोरूम के शुभारंभ पर अपनी शुभकामनाएं दीं और व्यवसाय की उज्ज्वल सफलता की कामना की

आईजी देवीपाटन की जनसुनवाई: हर फरियादी की बात गंभीरता से सुनी, निष्पक्ष व त्वरित निस्तारण के दिए सख्त निर्देश



स्वदेश प्रेम, रमजान अली। गोंडा पुलिस, 23 जुलाई। गुलिस, देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा श्री अशोक कुमार ने गुरुवार को परिक्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान दूर-दराज से पहुंचे शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों के निष्पक्ष, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए पुलिस महानिरीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। आईजी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रत्येक शिकायत का विधिबद्ध एवं संतोषजनक निस्तारण कराया जाए, ताकि आमजन का पुलिस प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।

पुलिस की जांच में पता चला कि युवक नशे में था। उसे शराब पीने को पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने बदन सिंह बड़ो का नाम लेकर रंगदारी मांग ली। पूछताछ में सामने आया कि युवक किठौर के महलवाला का रहने वाला रोहित त्यागी है। रोहित ने पुलिस पूछताछ में बताया कि शराब पीने से के लिए पैसे चाहिए थे। वह खुद मांगता तो कोई पैसे नहीं देता। इसलिए बदन सिंह बड़ो का नाम लेकर रकम मांगी गई थी। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



खुशकिस्मत हूं की टाइपकास्ट नहीं हुई

रसिका दुगल ने गहरे और हटकर किरदारों को चुनकर अपना करियर बनाया है। लेकिन वह मानती हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका करियर किस दिशा में जा रहा है। जहां 'मिर्जापुर' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, वहीं रसिका का कहना है कि 'मंटो' ने उन्हें उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकाला। रसिका ने उन किरदारों के बारे में बात की जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी।

‘मंटो’ ऐसे समय में मिली जब सबसे ज्यादा जरूरत थी बातचीत में अपने करियर के लिए सबसे अहम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए रसिका ने कहा कि 'मिर्जापुर' बेशक सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंची। लेकिन 'मंटो' ऐसे समय में मिली जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लोगों ने मुझे एक अलग नजरिए से देखा और जो बहुत बड़े दर्शकों तक पहुंचा, वह निश्चित रूप से 'मिर्जापुर' था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज ने मुझे उस मुश्किल दौर से बाहर निकाला, वह 'मंटो' थी। रसिका का कहना है कि वह खुशकिस्मत रही कि एक ही तरह के किरदारों में बंधकर नहीं रह गई। 'मिर्जापुर' में एक्टरों को उनके किरदारों के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं लकी थी क्योंकि 'मंटो', 'मिर्जापुर' और 'दिल्ली क्राइम' लगभग एक ही समय पर रिलीज हुए थे। 'दिल्ली क्राइम' और 'मिर्जापुर' में बिल्कुल अलग-अलग किरदार थे। इसलिए मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे उस विविधता को आजमाने और दिखाने का मौका मिला। दोनों ने अपने-अपने तरीके से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 'दिल्ली क्राइम' एक बहुत ही शानदार शो है। रसिका ने माना कि टाइपकास्टिंग से बचना हमेशा उनकी प्राथमिकता नहीं थी।



लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर शहनाज गिल ने बताया अपना अनुभव

बॉलीवुड अभिनेत्री शहनाज गिल ने हाल ही में लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि इसे लेकर मन में एक डर आता है।

जब शहनाज से पूछा गया कि क्या दूर रहने से प्यार बढ़ता है या कम हो जाता है? इस पर उन्होंने कहा, 'जब दो लोग एक-दूसरे से दूर होते हैं, तो प्यार और पार्टनर की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक डर भी मन में आता है कि सामने वाला इंसान पीछे क्या कर रहा होगा। इसलिए दूरी से शक भी बढ़ जाता है।' शहनाज ने कहा, 'मेरा मानना है कि अगर प्यार सच्चा हो और पार्टनर पास हो, तो रिश्ते में किसी दूरी की जरूरत नहीं होती।'

आज के दौर में प्यार

जब शहनाज से पूछा गया कि आज के डेटिंग ऐप्स के जमाने में क्या ऐसा सच्चा प्यार मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि प्यार किसी भी तरह का हो, चाहे पुराने जमाने का या आज के दौर का बस दिल में सच्चा प्यार होना चाहिए। फिल्म 'इश्कनामा' एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जा रही है। यह फिल्म निम्मा और नसीमा नाम के

दो प्रेमियों की असल जिंदगी की कहानी है। इसकी कहानी 1981 से 1988 के बीच भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के आस-पास की है, जो प्यार, उनके त्याग और मजबूरी में अलग होने के दर्द को दिखाती है। किस किताब पर आधारित है 'इश्कनामा' फिल्म 'इश्कनामा', 'हिंद पाक बॉर्डरनामा' नाम की किताब पर बनी बताई जा रही है। इस फिल्म में शहनाज गिल के साथ जय रंधावा और सौरभ सचदेवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर अरविंद एस. खेरा हैं। फिल्म का म्यूजिक बी प्राक ने दिया है और गाने जानी ने लिखे हैं। यह फिल्म 24 जुलाई को भारत, कनाडा और यूके समेत दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



‘आर्टिकल 370’ के लिए नेशनल अवॉर्ड में जिंदगी भर याद रखूंगी

अभिनेत्री यामी गौतम को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है। उन्हें फिल्म 'आर्टिकल 370' में बेहतरीन अदाकारी करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा उनकी फिल्म 'आर्टिकल 370' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इस कामयाबी से अभिनेत्री खुश हैं। पुरस्कार मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। अभिनेत्री ने



पुरस्कार मिलने के बाद एक्स पर लिखा 'हर सफर में एक ऐसा पल आता है, जो आपको याद दिलाता है कि आपने हार क्यों नहीं मानी। आज मेरे लिए वही पल है। 'आर्टिकल 370' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना मेरे लिए एक ऐसा सम्मान है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी।' उन्होंने आगे लिखा 'चौदह वर्षों से, मैंने बस अपने काम के प्रति ईमानदार रहने, ईमानदारी से काम करने और अपनी परफॉर्मेंस को ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। यह सम्मान उम्मीद, हिम्मत, मजबूती और सिनेमा के लिए अटूट प्यार से भरे सफर का नतीजा लगता है। यह एक ऐसा

सपना है, जिसे मैंने वर्षों से अपने दिल में संजोकर रखा था और आज, मैं इसे बहुत आभार और विनम्रता के साथ स्वीकार कर रही हूँ।'

यामी ने बताया आभार

उन्होंने फिल्म 'आर्टिकल 370' को चुनने के लिए और इसे पुरस्कार देने के लिए आभार जताया है। उन्होंने लिखा 'मेरे परिवार, मेरी टीम, मेरे शुभचिंतकों और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने उतार-चढ़ाव के हर दौर में मुझ पर भरोसा किया। आपके भरोसे ने मुझे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दी, तब भी जब मंजिल बहुत दूर लगती थी।'

रियलिटी शो में आता है कलाकारों का असली चेहरा, किरदार से अलग होती है पहचान

टीवी अभिनेत्री ईशा सिंह 'बिग बॉस 18' में नजर आने के बाद काफी सुर्खियों में रही हैं। अब उन्होंने रियलिटी शो और एक्टिंग की दुनिया के बीच के फर्क को लेकर अपनी राय साझा की है।

उनका मानना है कि रियलिटी शो कलाकार के असली स्वभाव को समझने का मौका देते हैं। जब कोई कलाकार रियलिटी शो में आता है तो दर्शक उसे उसके निभाए किरदारों से अलग एक इंसान के रूप में जान पाते हैं। इंटरव्यू में ईशा सिंह से जब पूछा गया कि क्या रियलिटी शो किसी अभिनेता या अभिनेत्री को ज्यादा लोकप्रिय बनाने में मदद करते हैं, इस पर उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि इससे किसी कलाकार की लोकप्रियता कितनी बढ़ती है, लेकिन दर्शकों को अपने पसंदीदा सितारों की निजी जिंदगी के बारे में जानने में हमेशा दिलचस्पी रहती है। लोग बिहाइंड द सीन्स जैसी चीजें इसलिए देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वे कलाकार को और करीब से जानना चाहते हैं। जब कोई कलाकार किसी रियलिटी शो में आता है तो दर्शकों को उसके असली स्वभाव, व्यवहार और पसंद-नापसंद को समझने का मौका मिलता है।' अभिनेत्री ने उदाहरण देते हुए कहा, 'दर्शक

मेरे निभाए किरदारों जैसे जुही और सैयम को जानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ईशा कैसी हैं, उनका व्यवहार कैसा है और वह किस तरह की इंसान हैं, यह जानने का मौका रियलिटी शो से ही मिलता है। रियलिटी शो में कोई किरदार नहीं होता और न ही कोई अभिनय का पर्दा होता है, बल्कि वहां कलाकार खुद के रूप में सामने आता है।' ईशा सिंह ने कहा, 'यही वजह है कि दर्शकों का कलाकारों के साथ एक अलग जुड़ाव बन जाता है। लोग सिर्फ किसी कलाकार का काम ही नहीं देखना चाहते, बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि वह अपनी निजी जिंदगी में कैसा है। दर्शकों को यह जानने में भी दिलचस्पी होती है कि कोई कलाकार क्या पहनता है, कैसे तैयार होता है, क्या खाता है और उसका व्यवहार कैसा है।' उन्होंने आगे कहा, 'रियलिटी शो और फिक्शन शो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। दोनों का अपना अलग महत्व और अलग दर्शक वर्ग होता है। रियलिटी शो में कलाकार का निजी पक्ष सामने आता है, जबकि अभिनय में कलाकार किसी कहानी और किरदार को जीता है। रियलिटी शो की अपनी अलग ऑडियंस होती है। आज कई तरह के रियलिटी शो बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक्टिंग पूरी तरह अलग चीज है। यह बिल्कुल अलग तरह का क्षेत्र है।'

‘आर्टिकल 370’ को तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर गदगद हैं आदित्य धर



बीते दिनों 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं के नाम का एलान हुआ। यामी गौतम अभिनीत फिल्म 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा फिल्म ने दो और पुरस्कार जीते हैं। इसी फिल्म के लिए यामी गौतम के नाम का एलान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर किया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए शशवत सचदेव ने पुरस्कार जीता है। इस पर आदित्य धर ने रिएक्शन दिया है।

आदित्य धर ने जताई खुशी

बता दें कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार साल 2024 के लिए प्रदान किए जाएंगे। विजेताओं

का एलान हो चुका है। 'आर्टिकल 370' को तीन पुरस्कार मिलने पर आदित्य धर गदगद हैं। उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है। 'धुरंधर' डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर खुशी जताई है और यह वादा किया है कि वे इसी तरह की कहानियां लाते रहेंगे।

शब्दों में बयां करना मुश्किल

आदित्य धर ने लिखा है, 'फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए तीन नेशनल अवॉर्ड जीतना एक ऐसा पल है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह अनुभव मुझे विनम्र और भावुक बनाता है और मेरा दिल गहरे आभार से भर देता है। जब हमने यह फिल्म बनाने का फैसला किया, तो हमारा मकसद अवॉर्ड पाना नहीं था। हम ईमानदारी, हिम्मत और सच्चाई के साथ एक कहानी कहने के पक्के इरादे से प्रेरित थे। यह देखना वाकई बहुत सुखद है कि देश भर के दर्शकों ने इस सफर को पसंद किया और अब इसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है।

ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे

आदित्य ने आगे लिखा है, 'जियो स्टूडियोज में

हमारे पार्टनर्स, खासकर ज्योति देशपांडे का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अटूट भरोसे के साथ इस फिल्म का साथ दिया और सार्थक सिनेमा को बढ़ावा दिया। पुरस्कार मिलना खुशी तो है ही, साथ ही वे आगे की जिम्मेदारी की याद भी दिलाते हैं। यह सम्मान हमारे इस भरोसे को और मजबूत करता है कि ईमानदारी, पक्के इरादे और मकसद के साथ कही गई

कहानियां हमेशा अपनी जगह बना ही लेती हैं। यह मंजिल नहीं है। यह एक वादा है कि हम नई सीमाएं तय करते रहेंगे, ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे, जो मायने रखती हैं और ऐसा सिनेमा बनाते रहेंगे जो बातचीत शुरू करें। भावनाओं को जगाए और एक गहरी छाप छोड़े। दिल की गहराइयों से... धन्यवाद। यह सम्मान हम सभी का है। जय हिंद।'

यामी और प्रियामणि के अभिनय को सराहा

इस शानदार सम्मान के लिए सम्मानित जूरी का और उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 'आर्टिकल 370' देखी, उसे सपोर्ट किया, उस पर चर्चा की और उसमें भरोसा जताया। आपके प्यार ने इस फिल्म को स्क्रीन से परे एक नई जिंदगी दी। यह सम्मान हमारे बेहतरीन डायरेक्टर, आदित्य सुहास जांभले का है, जिसकी सोच और पक्के इरादे ने हर फ्रेम को आकार दिया। यामी गौतम और प्रियामणि का भी शुक्रिया, जिन्होंने अपनी एक्टिंग में इतनी गहराई, मजबूती और सच्चाई दिखाई। शाश्वत सचदेव का भी धन्यवाद, जिनका संगीत हमारी कहानी कहने की कला की जान बन गया। हमारी कास्ट और क्रेडिट्स के हर सदस्य का भी शुक्रिया, जिनकी लगातार मेहनत, जुनून और भरोसे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।



संपादकीय

समाज सुधार का समय: नशामुक्त युवा, मर्यादित संस्कृति और अपराधमुक्त हरियाणा



सम्पादक
जान मोहम्मद

किस्ती भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। यदि युवाओं के हाथों में शिक्षा, रोजगार, संस्कार और अवसर हों तो वही युवा राज्य और राष्ट्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाते हैं। लेकिन यदि उन्हीं युवाओं के हाथों में नशा, अपराध और भटकाव आ जाए तो वही शक्ति समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। आज हरियाणा सहित देश के अनेक हिस्सों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, गैंगस्टर संस्कृति का प्रभाव, सोशल मीडिया पर अपराध का महिमामंडन और मंचीय कार्यक्रमों में बढ़ती अश्लीलता ऐसे विषय हैं जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं का समाधान केवल कानून के भरोसे नहीं हो सकता, बल्कि समाज, परिवार, कलाकार, शिक्षण संस्थान और प्रशासन सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

सबसे पहली और सबसे बड़ी लड़ाई नशे के विरुद्ध होनी चाहिए। यदि नशा समाप्त हो जाए तो अपराधों का एक बड़ा कारण स्वतः समाप्त हो जाएगा। नशा केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। एक युवा जब नशे की गिरफ्त में आता है तो उसकी पढ़ाई छूटती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, परिवार आर्थिक संकट में फिर जाता है और धीरे-धीरे वह अपराध की दुनिया की ओर बढ़ने लगता है। अनेक बार चोरी, लूट, हिंसा और हत्या जैसे अपराधों के पीछे नशे की तन प्रमुख कारण बन जाती है। इसलिए नशामुक्त समाज केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक विकास का भी विषय है। हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी पढ़-लिखकर समाजजनक जीवन जिए। कोई भी मां यह नहीं चाहती कि उसका बेटा नशे का शिकार होकर उसकी आँखों के सामने बर्बाद हो जाए। इसलिए सरकार, प्रशासन और समाज का पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जाए। यदि युवा सुरक्षित रहेगा तो परिवार सुरक्षित रहेगा और यदि परिवार सुरक्षित रहेगा तो समाज और राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। ऐसी व्यवस्था विकसित होनी चाहिए कि किसी घर की माँ अपने बेटे की लाश देखकर न रोए और किसी पिता को अपने बेटे के भविष्य के लिए निराश न होना पड़े।

नशे के विरुद्ध केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नियमित जागरूकता अभियान चलाने होंगे। विद्यार्थियों को खेल, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियों और कौशल विकास से जोड़ना होगा। युवाओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि जीवन की असली सफलता नशे में नहीं, बल्कि मेहनत, शिक्षा और अनुशासन में है। गांवों और शहरों में नशामुक्ति केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाना होगा ताकि जो लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, उन्हें सम्मानजनक मध्यस्थता में वापस लाया जा सके।

इसके साथ ही गैंगस्टर संस्कृति भी आज एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन चुकी है। कुछ अपराधी समूह नौरो-भाले और नवालिग बच्चों के अपने जाल में फंसाकर उनका उपयोग अपराधों में करते हैं। कम उम्र के बच्चों को आसान पैसे, महंगी गाड़ियाँ, हथियारों का आभूषण और सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि का लालच देकर अपराध की राह पर धकेल दिया जाता है। कई बार इन बच्चों को यह भी समझ नहीं होता कि वे किस दलदल में उतर रहे हैं। जब तक उन्हें वास्तविकता का एहसास नहीं है, जब तक उनका भविष्य, उनका परिवार और उनका जीवन संकट में पड़ चुका होता है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि अपराध करने वाले बड़े लोग स्वयं पीछे रहते हैं और मासूम बच्चों को आगे कर देते हैं। अपराध का दंड अंततः उन्हीं बच्चों और उनसे परिवारों को भुगतान पड़ता है। एक नवालिग के अपराध में शामिल होने से उसका पूरा परिवार सामाजिक अपमान, आर्थिक कठिनायों और मानसिक पीड़ा से गुजरता है। इसलिए ऐसे अपराधी गिराओं पर कठोर कार्रवाई सही की मांग है। पुलिस प्रशासन लगातार अपराध निर्वन्धन के लिए प्रयास करता है, लेकिन समाज का संयोग भी उतना ही आवश्यक है। यदि किसी क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियाँ दिखाई दें, यदि कोई व्यक्ति बच्चों को अपराध के लिए बलवान-सुल्लाकर अपने साथ जोड़ रहा हो या अवैध हथियारों और नशे का कारोबार कर रहा हो, तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। अपराधियों के विरुद्ध समाज की सामूहिक जागरूकता ही सबसे प्रभावी हथियार बन सकती है। सोशल मीडिया ने भी इस समस्या को कहीं न कहीं बढ़ाया है। आज कुछ लोग गैंगस्टरों को नायक की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनके गानों, वीडियो और पोस्टों में अपराध को शक्ति और सम्मान का प्रतीक दिखाया जाता है। यह प्रवृत्ति युवाओं के मन पर गलत प्रभाव डालती है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज ऐसे मिथकों को तोड़े और युवाओं को वास्तविक नायकों से परिचित करए—वे लोग जिन्होंने शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना, कृषि, उद्योग और सामाजिक सेवा के माध्यम से देश का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मंचीय आवाजों की दिशा पर भी गंभीर चिंतन आवश्यक है। हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध रही है। यहां की रामली, लोकगीत, सांग, लोकनृत्य और परंपरिक कलाएं भारतीय संस्कृति की पट्टन हैं। इन लोक परंपराओं में मनोरंजन के साथ-साथ नैतिक शिक्षा, सामाजिक संदेश और सांस्कृतिक गरिमा भी होती थी।



उप संपादक
स्वदेश प्रेम
प कुमार श्रीवास्तव

देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठे गंभीर सवालों के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। नीट-



कांतिलाल मांडोत

सो शल मीडिया से ब्रेनवॉश और त्रि तक आतंक का नया जाल, लो सुरक्षा एजेंसियां हर साजिश को

नाकाम...

आतंकवाद का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। कभी सीमा पार से घुसपैठ की तकनीक और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण इसके प्रमुख हथियार थे, लेकिन तकनीक के आतंकवादी सांठनों के एप रास्ते उपलब्ध हैं। अब आतंक का नेटवर्क बंदूक और कहीं अधिक मोबाइल फोन, सोशल एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप, कृत्रिम बुद्धि जांच एजेंसी के सहारे संचालित हो रहा है। जांच एजेंसी (एनआइए) की हालिया कार्यविधि मालाओं में दायर आरोपपत्रों ने न केवल स्वरूप की स्पष्ट तस्वीर सामने रखी है। उल्टा कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठनों की सुनिश्चित शी-एप मॉडल के माध्यम से संचालित होने वाले जाल में फँसाने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क स्थापित करने के लिए वे फ़ैसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल+ है, फिर एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर वैचारिक फैलावर ब्रेनवाश किया जाता है और जांच एजेंसी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह नया मॉडल केवल तकनीकी बदल बल्कि आतंकवाद की रणनीति में आया भी है। पहले आतंकवादी संगठनों को भर्ती के लिए भौतिक नेटवर्क की आवश्यकत जबकि अब इंटरनेट ने दुनिया के किसी

पूजी पेपर लोक प्रकरण के बाद छात्रों के देखरवाणी आंदोलन, सामाजिक कार्यकर्ता सुनम बांगुचर के अंशान और बड़ते जेदबाद के बीच सरकार ने एक ही दिन में कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर संकेत दिया है कि अब परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुस्थिति और जाबदेह बनाया जाएगा।

सरकार ने सबसे पहले पेपर लोक जैसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिया, ताकि परीक्षा संबंधी अपराधों में न्यायिक जांच सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में उच्च शिक्षा सचिव विनोत प्रोशा को उनके पद से हटया गया, जिसे जांचासिनिक जाबदेही तय करने की दश्री में बड़ा कदम बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट किया कि पेपर लोक जैसी घटनाओं के खिलफ कोठर कागान और सुख कारंबाई के लिए सरकार प्रबिबद्ध है तथा छात्रों का एक भी रैशनिक

वर्ष बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा।
लेकर, लंबे समय से छात्रों की मांगों को
उत्तर कर सका कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता
सोमन वांग्चुक ने सरकार के साथ हुई वार्ता
के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया।
सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर
कारवायु का रुख अपनाने हुए परीक्षा
प्रणाली में व्यापक सुधार का भरोसा दिया।
इस घटनाक्रम ने संकेत दिया कि सरकार
अब केवल तात्कालिक कार्रवाई तक
सिमित नहीं रहना चाहती, बल्कि स्थायी
सुधारों की दिशा में भी आगे बढ़ रही है।
इसी क्रम में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
(एनटीए) की कार्यप्रणाली में व्यापक
बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत भविष्य में
एनटीए की परीक्षाओं को यूपीएससी की तर्ज
पर अधिक फुलप्रूफ बनाया जाएगा। परीक्षा
संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्र प्रबंधन
और निगरानी प्रणाली की पूर्ण समीक्षा होगी।

किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही पर कठोर कार्रवाई होगी। सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे इस सुधार खाके में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों से प्राप्त 37 हजार से अधिक सुझावों को शामिल किया गया है। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, तकनीकी निगरानी, डिजिटल ऑफ्ट, संचालन प्रणाली और पाठ्यपद्धति बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत बनाने की तैयारी है।

नीट पेपर लीक मामले की जांच में भी एजेंसियाँ लगाकर कार्रवाई कर रही हैं। जांच के दौरान कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी स्तर पर

बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संस्थागत सुधार लागू किए जाएंगे। लेकिन संस्था ही जौंच एजेंसीओं पर भी सख्त कार्रवाई करेगा।

बकरा रहता है नोट परीक्षा 2024 के पेपर लीक में मुख्य आरोपी संजीव कुमार पंडा संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीनचिट दे दी है, सीबीआई का कहना है की संजीव की भूमिका नहीं मिल प्रश्न पत्र लीक में इसीलिए उसे क्लीनचिट दी जाती है। विशेषज्ञ का मानना है कि यदि औपचारिक समर्थन के से लागू होते हैं और जवाबदेही की व्यवस्था प्रभावित रहती है, तो देश की प्रतिष्ठित परीक्षा प्रणाली में हानि होगी।

हार्दिस और विश्वसनीयता दोनों मजबूत पाठों। लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह संस्था महत्वपूर्ण है कि उनकी मेहनत की रक्षा केवल सख्त कानून से नहीं, बल्कि मजबूत और जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था से ही संभव है।

आतंकवाद का बदलता चेहरा और भारत की जीरो टॉलरेंस नीति

बेठे व्यक्ति तक उनकी पहुँच आसान बना दी है। सोशल मीडिया पर सामान्य धार्मिक या वैचारिक सामग्री के माध्यम से युवाओं का विश्वास जीतने का प्रयास किया जाता है। धीरे-धीरे उन्हें 'बंद समूहों' में जोड़ा जाता है जहाँ उन और हिंसक विचारधारा से परिचित कराया जाता है। इसके बाद हथियारों, विस्फोटकों और अतृक गतिविधियों से संबंधित सामग्री साझा कर उन्हें हिंसा के रास्ते पर धकेलने की कोशिश की जाती है।

एनआईए की जांच में सामने आए विभिन्न मांड्यूल इस ग़ुप्त ख़तरे की गंभीरता को दर्शाते हैं। तमिलनाडु में ऐसे समूहों का पता चला जिन्हें सोशलि मोडिया और एंक्रिप्टेड एप के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया। विजयवाड़ा से जुड़े मामले में विदेशी हैंडलरों के संजय, भारत में कड़पूर फैलाने और प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने जैसे योजनाओं का खुलासा हुआ। मंगलुरु मांड्यूल में डिजिटल लोफ़रों के माध्यम से विस्फोटक बनाने की योजनाओं और क्रिप्टोकॉइन्स के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात सामने आई। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि आतंकवादी संगठन अब पारंपरिक नेटवर्क से अधिक डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होते जा रहे हैं।

इन माँदयूल का सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि इनके निशाने पर 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के पढ़-लिखे युवा हैं। यह वर्ग इंटरनेट और सोशल मीडिया का सबसे अधिक उपयोग करता है। आतंकवादियों संगठन इसी मनोविज्ञान का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। वे पहले धार्मिक, सामाजिक या भाषानात्मक विषयों पर चर्चा के बहाने संपर्क स्थापित करते हैं और धीरे-धीरे युवाओं को कट्टर विचारधारा की ओर मोड़ते हैं। कई बार यह पूरी प्रक्रिया इतनी सुनिश्चित होती है कि व्यक्ति को स्वयं यह एहसास नहीं होता कि वह किस प्रकार एक खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा बनता जा रहा है।

तकनीक के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी आतंकवाद के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहा है। फर्जी वीडियो, परिवर्तित आवाज, नकली पहचान और स्वचालित संदेशों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। एन्क्रिप्टेड संचार के

कारण जांच एजेंसियों के लिए इन नेटवर्क तक पहुंचना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो जाता है। वहाँ क्रिप्टोकैरेंसी के माध्यम से होने वाला लेन-देन पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से अलग होने के कारण इसकी निगरानी भी चुनौतीपूर्ण रहती है। यही कारण है कि आधुनिक आतंकवाद केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा और तकनीकी क्षमता का भी विषय बन चुका है।

हालांकि इन चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा और जांच एजेंसियों की सतर्कता लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, विभिन्न राज्यों की आतंकवाद निरोधी इकाइयाँ, खुफिया एजेंसियाँ और साइबर विशेषज्ञ समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। देशभर में लगातार छापेमारी, संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों की निगरानी, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान और समय रहते कार्रवाई के कारण अनेक साजिशों को विफल किया गया है। वह स्पष्ट संकेत है कि आतंकवादों से निपटने वाले जितनी संश्लेषित तकनीक अपनाएँ, भारतीय सुरक्षा तंत्र भी उसी गति से अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के प्रति ज़ोरों टॉलर्स की नीति को पूरी दृढ़ता के साथ लागू किया है। इस नीति का मूल उद्देश्य यह है कि आतंकवाद के प्रति किसी भी स्तर पर सह्यता न बरती जाए। चाहे सीमा पार से संचालित नेटवर्क हों, देश के भीतर सक्रिय मौजूद हों या आर्थिक सहायता पहुंचाने वाले तंत्र, सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। यही कारण है कि अनेक आतंकी संगठन आज पहले की तुलना में काफी कमजोर पड़े हैं। उनके पारंपरिक नेटवर्क लगातार ध्वस्त हुए हैं और उन्हें नए-नए तरीके अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

यह भी सच है कि आतंकवादों से निपटने वाली गतिविधियाँ जारी रखने के लिए लगातार नए रास्ते खोज रहे हैं। कभी सोशल मीडिया, कभी एंक्रिप्टेड ऐप, कभी क्रिप्टोकैरेंसी के माध्यम से कभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर वे अपनी मौजूदगी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत की खुफिया और जांच एजेंसियाँ भी समान रूप से सज्ज हैं। वर्षों के अनुभव, आधुनिक तकनीक और मजबूत समन्वय के कारण वे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में

पहले से कहां अधिक सक्षम हुई हैं। अनुभवी अधिकारी व्यवहार, डिजिटल गतिविधियाँ और संदिग्ध संपर्कों का विश्लेषण कर समय रहते खतरे का आकलन कर लेते हैं। यही सतर्कता अनेक संभावित घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोक देती है। आतंकवाद के विरुद्ध संपर्क केवल सुरक्षा एजेंसियों का दायित्व नहीं है बल्कि समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संगठन और सामाजिक संस्थाएँ युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। डिजिटल सक्षमता, तथ्य आधारित सोच और अपव्याहों से बचने की आदत विमिश्रित करना आज की आवश्यकता है। यदि समाज जागरूक रहेगा तो आतंकवादी संगठनों के लिए युवाओं को भ्रमित करना कठिन हो जाएगा। भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह आतंकवाद के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करेगा। सीमा पर कठोर सुरक्षा व्यवस्था, देश के भीतर मजबूत जांच तंत्र, आधुनिक तकनीक का उपयोग और जोरों टॉलरेंस की नीति ने आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को लगातार सीमित किया है। यदि कोई अतिरिक्त नेवर्क भूमित होकर छिपे का प्रयास भी करता है तो सुरक्षा एजेंसियाँ उसे खोज निकालने और कानून के दायरे में लाने के लिए निरंतर सक्रिय रहती हैं। यही दृढ़ इच्छाशक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

आतंकवाद का स्वरूप उदाह्रिय समाज में भ्रम, अस्थिरता और विभाजन पैदा करना ही होता है। इसके मुकाबले के लिए केवल हथियार नहीं बल्कि तकनीकी दक्षता, मजबूत सूचना तंत्र, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। भारत ने इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यही कारण है कि आतंकवाद का नया डिजिटल मॉडल भी भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के सामने लम्बे समय तक सफल नहीं हो पाएगा। ज्योर्ज टॉलंस की नीति, सार्वभौम सुशासन की प्रतिबद्धता और जागरूक नागरिकों के सहयोग से आतंकवाद के हर नए रूप का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। यही राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार-स्तम्भकार हैं)

संवाद से सशक्त होगा लोकतंत्र, हिंसा से नहीं

हिल्ली के जंतर-मंतर से संसद भवन में अहिलेन के दौरान जो तनाव, हिंसक घटनाएँ देखने को मिलीं कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि भारत की परिपक्वता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए जाते। प्रदर्शनकारीयों के बीच टकराव, बैरिकेड प्रयास, मेट्रो स्टेशन में जबरन प्रवेश की कोशिशें द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग-ये सब लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुरूप नहीं करतें, जिसकी आधारशिला अहिंसा, संवाद और सहयोग-मार्गदर्शकों पर रखी गई है। भारत आज आजाद वर्ष 2047 की ओर बढ़ रहा है। यह केवल महाराष्ट्र बनने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि परिपक्वता की कसौटी पर भी स्वयं को सिद्धांतबद्ध है। यदि हम आज भी अशहान्ति की ओर और अराजकता के माध्यम से व्यक्त करेंगे, तो आत्मा कमजोर होगी। लोकतंत्र की शक्ति संसद प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विचारों की शक्ति संस्कृति और संवैधानिक प्रक्रियाओं में निहित रहती है। राहुल गांधी द्वारा नीट पेपर लोक प्रकरण की कोशिश-प्रदर्शन के दौरान अवाचन असहयोग का प्रयोग साधन-प्रदर्शन में आवास के निकट धरने पर संसद की बजाय सड़क को राजनीतिक स्थान बनाना अनेक गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जिससे पहले कांग्रेस का ताना फाँटें के तथाकथित कार्यकर्ताओं ने संसद चले मार्च के दौरान अराजक एवं हिंसक माहौल बनाने की घटनाएँ देखी उससे यह आश्चर्य नहीं हुई कि कुकुट शक्तिपूर्ण भारत में जो नेपाल जैसी अराजक प्रक्रिया करने को उजावले हैं। सरकार की सतर्कता एवं एजेंसियों की समर्थन रहते की यह कार्यवाई से, के बावजूद, इस तरह संसद को टाल दिया दिल्ली लंबे समय तक हिंसा और आशक्ति का सत्तरी थी। देश पहले भी नागरिकता संसद (सीएए) के विरोध के दौरान शाहीन बाग दिनों तक एक प्रमुख सड़क के अवरुद्ध रहने आम नागरिकों को हुई भारी कठिनाई का सामना चुका है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध निर्विवाद है, लेकिन उसका स्थान संसद, संवैधानिक संस्थाएँ हैं। न कि सड़क पर अराजकता। विपक्ष यदि बार-बार ऐसे अ-प्रोत्साहित करता है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक उद्देश्य-निष्ठ विमर्शों को मजबूत राजनीतिक ध्येयकरण और अस्थिरता के



जनता अपेक्षा करती है कि सभी दल संसद को सर्वोच्च मंच मानते हुए वहीं जवाबदेही सुनिश्चित करें।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण और निरन्तर सभा करने का अधिकार देता है। यह अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। किंतु प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य और मर्यादा भी जुड़ी होती है। प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, पुलिस से टकराव करना, हिंसा फैलाना अथवा आम नागरिकों के जीवन को बाधित करना किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक आचरण नहीं कहा जा सकता। यह आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति खो देता है, तो उसकी मर्यादा भी समाज की सहायतापूर्ण खो बैठती है। यह भी उनाई ही सत्य है कि लोकतंत्र केवल जनता के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी उत्तरदायित्व का नाम है। सरकार को भी आंदोलनों के केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं देखना चाहिए। जब भी किसी वर्ष, विपक्षक युवाओं और छात्रों में असंतोष उत्पन्न हो, तो उसका समर्थन रहते समाधान खोजने का प्रयास होना चाहिए। संवाद के दरवाजे जितनी जल्दी खुलेंगे, टकराव की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी शक्ति उसका वैयक्तिक संवेदनशीलता और संवाद की इच्छा होती है। इतिहास साक्षी है कि भारत के अधिकांश सफल जनआंदोलन अहिंसा और संवाद की शक्ति से ही सफल हुए हैं। महात्मा गांधी ने विश्व को यह संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़े अस्त्र हैं। वर्ष 2011 का अना-हजारे का प्रश्नकार विरोधी आंदोलन भी इसका उदाहरण है। लाखों लोग सड़क पर उठे, लेकिन आंदोलन का नैतिक

मूल उसकी शांति और अनुशासन में था। उसी कारण सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना पड़ा और पूरे देश एक समकारता के बहस प्रारंभ हुए। इसके विपरीत जहाँ-जहाँ आंदोलनों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, वहाँ उनका मूल उद्देश्य पीछे छूट गया और चर्चा केवल हिंसा तक सीमित होकर रह गई। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं, जो सामान्य और भोली-भाली जनता एवं देश के युवाओं को हिंसा की ओर धकेल देती हैं? कौन-से तत्व आंदोलनों की दिशा बदलकर उन्हें आराजकता में परिवर्तित कर देते हैं? यह चिंतन केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए। लोकतंत्र में असमर्थित स्वाभाविक है, लेकिन यदि आहमर्ग के चयन पर राष्ट्रविरोधी, आराजक अथवा हिंसक तत्व सक्रिय हो जाएँ, तो उसे निरंत्रित करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य दायित्व बन जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ आराजकता की स्वतंत्रता नहीं हो सकता। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। जंतर-मंतर, लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक स्थल है। यदि इन दोनों के बीच हिंसा, तोड़फोड़ एवं आराजकता का दृश्य निर्मित होता है, तो यह केवल राजधानी की घटना नहीं रहती, बल्कि पूरे देश और विश्व के सामने भारतीय लोकतंत्र की छवि को प्रभावित करती है। लोकतंत्र की गरिमा इस बात में नहीं कि कौन अधिक आक्रामक है, बल्कि इस बात में कि कौन अधिक संयमित और उत्तरदायी है। राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के दो पहिए हैं। यदि दोनों के बीच संवाद समाप्त हो जाएगा, तो लोकतंत्र टकराएगा का अखाड़ा बन जाएगा। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि

रचनात्मक विवेक प्रस्तुत करना भी है। उसी प्रकार सरकार का दायित्व केवल शक्ति प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि असहमति को सम्मानपूर्वक सुनना भी है। लोकतंत्र में किसी की पूर्ण विजय या पूर्ण पराजय नहीं होती, यहां अंततः संवाद, सहमति और समाधान ही सबसे बड़ी जीत होते हैं। छात्रों और युवाओं को समस्याओं का समाधान भी अत्यंत आवश्यक है। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा हैं। यदि उनको आशाओं और अपेक्षाओं की उपेक्षा होगी, तो असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह युवाओं से नियमित संवाद स्थापित करे, उनकी समस्याओं को सम्यक् ढंग से सुने और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए। वहीं युवाओं को भी यह समझना होगा कि हिंसा उनसे आंदोलन को सबसे बड़ी शत्रु है। पथर और लाठी किसी समस्या का समाधान नहीं करते, वे केवल संवाद के पुलों को तोड़ते हैं। आज आवश्यकता लोकतंत्र को अधिक परिपक्व बनाने की है। हमें ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित करनी होगी जिसमें विरोध हो, लेकिन वैमनस्य न हो। मतभेद हों, लेकिन मनभेद न हो। संघर्ष हो, लेकिन हिंसा न हो। लोकतंत्र में बहस जितनी प्रखर होगी, राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। किंतु बहस का स्थान यदि हिंसा ले लेगी, तो लोकतंत्र की आत्मा आहत होगी। जंतर-जंतर से संवाद तक को कुछ हद पर, उसे लोकतांत्रिक आदर्श नहीं कहा जा सकता। वह किसी परिपक्व राजनीतिक सोच का भी परिचायक नहीं है। राष्ट्र निर्माण का मार्ग उद्वारक नहीं, सहयोग है। हिंसा नहीं, सहमति है। उग्रता नहीं, उदारता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी पक्ष अपने-अपने आग्रहों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को संवर्धन रखें। आज देश को ऐसे नेतृत्व और ऐसी जनचेतना की आवश्यकता है जो संवाद को संघर्ष से ऊपर रखे। सरकार उदारता और संवेदनशीलता दिखाए, आंदोलनकारी संयम और अनुशासन अपनाए तथा राजनीतिक खेल अत्यंतकालिक लाभ के बजाय लोकतंत्र की दीर्घकालिक मजबूती को प्राथमिकता दें। वहीं भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की वास्तविक पहचान भी है और भविष्य की आवश्यकता भी। अतः यही कामना की जानी चाहिए कि जिन शक्तियों के कारण आंदोलनों में हिंसा और टहलान का वातावरण बनता है, उन्हें सुदृष्ट प्राण हो। सभी पक्ष संवाद की मेज पर बैठें, अपनी बात तर्क, तथ्यों और संवैधानिक मर्यादों के साथ रखें तथा समाधान का मार्ग खोजें। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय किसी पक्ष की जीत नहीं होती, बल्कि वह क्षण होता है जब विरोधी पक्ष भी एक-दूसरे का बात सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही आदर्श लोकतंत्र की पहचान है। और यही विकसित भारत की सबसे मजबूत बनावट भी है।



बीजों का सुरक्षित भण्डारण

पिंकी शर्माए पूनम यादव

पादप व्याधि विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोधनर-303329

कृषि में उन्नत बीज का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि उन्नत खेती को नीव एक अच्छे बीज पर ही आधारित है अतः बीजों का उचित भण्डारण बहुत जरूरी है। बीज पैदा करके उसे बोने तक भण्डारण का महत्वपूर्ण स्थान है। भण्डारित किये गये बीजों में ज्यादातर नुकसान कीटों द्वारा ही होता है। इसके अलावा चूहे, चिड़िया, दीमक एवं फंसे आदि द्वारा भी नुकसान होता है। बीजों में कीट पैदा होने से बीजों की अंकुरण क्षमता, ओज एवं गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे खराब बीज न तो बाने लाइक और न ही खाने लाइक रहता है। इसलिए बीजों का भण्डारण पूरी सावधानी एवं देखरेख के साथ करनी चाहिए।

भण्डारित बीजों का नुकसान निम्न कारकों पर निर्भर करता है

1. बीज में अधिक आर्द्रता का होना।
2. खेत से ही संक्रमणित बीजों का भण्डारण
3. कीटों द्वारा संक्रमणित भण्डारण
4. भण्डारण के दौरान ताप एवं नमी में वृद्धि
5. भण्डारण में ऑक्सीजन की उपलब्धता



गोभीवर्गीय में पोषक तत्वों की आवश्यकता

भूरापन या ब्राउनिंग - यह समस्या गोभीवर्गीय फसलों में बोरान की कमी से होता है।

लक्षण - भूरापन में शुरुआत में फूल में जल अवशोषित धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि बाद में बड़े हो जाते हैं। इसके बाद तने में भी जल अवशोषित धब्बे पड़ते हैं तथा तना अंदर से खोखला हो जाता है। यदि भूरापन का प्रकोप ज्यादा होता है तो पूरा फूल में कुछ दिन बाद गुलाबी या भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं।

उपचार - बोरान की कमी को दूर करने के लिये 10-15 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टर भूमि में पौध रोपण के समय देना चाहिए अथवा जब फसल खड़ी हो 0.1 प्रतिशत बोरेक्स घोल का छिड़काव करना चाहिए प्रथम छिड़काव पौध रोपण के दो सप्ताह पश्चात और दूसरा छिड़काव फूल बनने से दो सप्ताह पहले करना चाहिए।

क्लिपटेल - यह लक्षण गोभीवर्गीय फसलों में मालीब्डिनम नामक तत्व की कमी के कारण होता है।

लक्षण - मुख्यतः मालीब्डिनम की कमी अम्लीय भूमि में हो जाती है अर्थात् मालीब्डिनम अनुपलब्ध रूप से हो जाता है, जिससे पौधे इस तत्व का अवशोषण नहीं कर पाते और क्लिपटेल के लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें शुरुआत में पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियाँ सिकुड़ कर सफेद पड़ने लगती हैं तथा कुछ दिन बाद पत्तियाँ अपना आकार

हमारे देश में अधिकतर किसान बीज स्वयं भण्डारित करते हैं और उनमें से अधिकतर बीजों का नुकसान कीटों से होता है। इन भण्डारित कीटों (खपर, सुरसुरी, घून, पंतगा, तीली आदि) को लगभग सभी किसान जानते हैं परन्तु इन कीटों के प्रकोप से बचने के लिए उचित भण्डारण एवं नियन्त्रण पर ध्यान देकर होने वाले भौतिक नुकसान के साथ-साथ बीज की अंकुरण क्षमता एवं ओज को भी बरकरार रख सकते हैं।

बीजों में लगने वाले प्रमुख कीट:-

भण्डारण के दौरान कीटों की लगभग चार दर्जन प्रजातियाँ बीजों को नुकसान पहुँचाती हैं। जिनमें से 10-15 प्रजातियाँ ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा विभिन्न प्रकार बीजों का नुकसान किया जाता है जिनमें से कुछ दानों को बाहर से खाते हैं। एवं कुछ अन्दर रहकर खाते हैं, जिनमें से प्रमुख कीट निम्नलिखित हैं।

1. टनाज की फसलों के बीज:- सूंड वाली सुरसुरी (सिटोफ्लिस, ओरायजी), चावल की सुरसुरी (ओराइजीफ्लिस सुरी नामेनसिस), गोदाम का पंतगा (केडरा कांटिला), मक्का का पंतगा (कोरसाइरा सिफेलोनिका), आटे का कीट (ट्राइबोलियम कैस्टेनियम), एवं खपर बीटल (ट्रोगोडरमा ग्रेनेरियम)
2. दलहनी फसलों के बीज:- दोरा (चार प्रजातियाँ- कैलोसोब्रक्स मैकुलेटस, कै. चाइनेनसिस, कै. एनालिए

एवं ब्रक्स पाइसोरम घुन (राइजोपरथा डोमिनिका), खपर बीटल (ट्रोगोडरमा ग्रेनेरियम), चावल पंतगा (कोरसाइरा सिफेलोनिका), एवं गोदाम का पंतगा (केडरा कांटिला) समय छाया में सुखाकर बोरों या थैलियों में भरकर भण्डारित करना चाहिए।

3. बीजों में उचित नमी:- बीजों को भण्डारित करने से पूर्व यह जाँच कर ले कि बीजों में सामान्यतः 10 प्रतिशत से अधिक नमी न हो, लेकिन मूँगफली एवं सरसों में 7 प्रतिशत एवं धान में 12 प्रतिशत एवं अरुण्डी में 8 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए।
4. भण्डारण कक्ष/पात्र को कीट मुक्त करना:- बीजों को जिस किसी कक्ष या पात्र में भण्डारित करना हो उसे भण्डारण पूर्व कीट मुक्त करना चाहिए। यदि भण्डारण कमरे या गोदाम में करना है तो उसे अच्छी तरह साफ करके मैलाधियान, क्लोरोपाइरीफॉस की 1 लीटर मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि बीज को मटके में भण्डारित करना हो तो मटके के अन्दर व बाहर 10 मि.ली. मैलाधियान का छिड़काव करें।
5. बीज भण्डारण के पश्चात् बीजों के नमी की वृद्धि रोकना एवं प्रधूमन करना:- बीज भरे बोरों या थैलियों को लकड़ी के तख्ते या पॉलीथीन चादर या बाँस का चटाई पर रखना चाहिए ताकि उनमें नमी का प्रवेश न हो। वर्षा ऋतु में भण्डारण में बीज होने के कारण कीटनाशी द्वारा उपचारित नहीं किया गया तो खेत से आये कीटों को नष्ट करने हेतु बीज को एल्युमिनियम फॉसफ़ाइड से 6-9 ग्राम मात्रा प्रति टन बीज के हिसाब से प्रधूमित करना चाहिए।
6. कीट प्रकोप पर निगरानी एवं कीटनाशी का छिड़काव:- भण्डार कक्ष को प्रत्येक 15 दिन में एक बार जरूर देखना चाहिए ताकि बीज में कीट या फंसे पर कोई जीवित कीट दिखे देने पर समय पर आवश्यकतानुसार कीटनाशी का छिड़काव या प्रधूमन किया जा सके। सामान्यतः भण्डार कक्ष एवं बोरों पर 15 दिन के अन्तराल पर मैलाधियान, क्लोरोपाइरीफॉस की 1 लीटर मात्रा 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बीज भण्डारण में प्रधूमन द्वारा कीटों से बचाव छिड़काव की अपेक्षा अधिक लाभकारी हैं इसलिए प्रधूमन का ही अधिकतम प्रयोग करें।

सावधानियाँ

1. बीजोपचार करते समय कीटनाशी को खुले हाथों से न छूए बल्कि किसी ड्रम में डालकर हिलाकर उपचारित करें।
2. उपचारित बोरियों या थैलियों पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
3. कीटनाशी बच्चों की पहुँच से दूर रखनी चाहिए।
4. कीटनाशकों का छिड़काव बदल-बदलकर करें।
5. प्रधूमन सदैव प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही करवाये।

बटनिंग - बटनिंग की समस्या गोभी वर्गीय फसलों के कई कारणों से होती है जैसे अधिक उम्र के रोप के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण या समय के अनुसार उचित किस्मों को ना लगाने से ऐसा होता है।

लक्षण - फूलों का विकसित ना होकर छोटा रह जाना बटनिंग कहलाता है। इसमें फूलों का आकार छोटा हो जाता है तथा कम विकसित पत्तियाँ होती हैं।

उपचार - बटनिंग को रोकने के लिये अग्रेती या पिछेती किस्मों अनुशंसित समय पर ही लगाएं, पौधे की वृद्धि चाहे वह नर्सरी में हो या खेत में नहीं रूकनी चाहिए। अधिक सिंचाई न करें। जो पौधा नर्सरी में अधिक दिन के हो उन्हें खेत में न लगाएं और नाइट्रोजन की उचित मात्रा पौधों को समय-समय पर दें।

रेसीयनेस - रेसीयनेस के लक्षण मुख्यतः वातावरण में अनुकूल तापमान की कमी, अधिक नाइट्रोजन देने के कारण तथा अधिक आर्द्रता के कारण होती हैं।

लक्षण - समय से पूर्व अविकसित कली को रेसीयनेस कहते हैं। इसमें फूल की ऊपरी सतह ढीली पड़ जाती है तथा सफेद छोटी कलिका बन जाती है।

उपचार - रेसीयनेस से उपचार के लिये उचित किस्म का चयन करें, समय पर पौधों की रोपाई करें, नाइट्रोजन की उचित मात्रा का प्रयोग करें तथा प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें।

बगीचों की स्थापना व प्रबंधन

नवीन उद्यान का विन्यास (लेआउट) कैसे करें-

नवीन उद्यान का विन्यास (रेखांकन) एक बहुत तकनीकी एवं महत्वपूर्ण क्रिया है। सर्वप्रथम क्षेत्रफल नाप लिया जाये तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें फिर चयनित फल एवं उसकी प्रजाति के आधार पर निर्धारित करें कि कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित करें। उद्यान रेखांकन करते समय निम्नलिखित उद्यान स्थल निर्धारित करें-

- सड़क एवं मार्ग
- फार्म हाउस (कार्यालय, भंडार, निवास) के लिए स्थल
- सिंचाई पद्धति के लिये पम्प हाउस, नलकूप, कुआँ, फार्म पाँड का स्थान निर्धारित करें। आजकल ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रचलित है। अतः उसके रेखांकन के लिये स्थल निर्धारित करें।

- जल निकास हेतु नाली आदि निर्माण हेतु स्थल
- पौधों को लगाने का स्थल
- फार्म पर कम्पोस्ट, नाडेप, केंचुआ खाद आदि का स्थल
- बगीचे के लिये स्वयं की रोपणी हेतु भी स्थल निर्धारित करें।

नवीन बगीचे के लिये प्रारंभिक तैयारियाँ - स्थल निर्धारण के पश्चात भूमि की सफाई, सर्वेक्षण, मिट्टी की परीक्षण, समतलीकरण, मिट्टी की जुताई, बगीचे के चारों ओर बागड़-तार, पत्थर की दीवार, वायु अवरोध लगाएं।

फल पौध रोपण - फल पौध रोपण की प्रचलित पद्धतियाँ निम्न प्रकार की हैं - **वर्गाकार पद्धति** - वृक्ष की आवश्यकता के अनुसार वर्ग का आकार रखा जाता है। इस पद्धति में पौधे वर्ग के कोने पर लगाए जाते हैं।



आयताकार- इस पद्धति में कतार से कतार की दूरी तथा पौधों की दूरी निर्धारित की जाती है।

त्रिभुजाकार या षट्भुजाकार पद्धति।

पंचवृक्षीया गौपूरक पद्धति- यह वर्गाकार की परिवर्तित पद्धति है इसके वर्ग के मध्य से एक और पौधा बनाया जाता है। आजकल संकर प्रजातियाँ आम में विकसित की गयी हैं उन्हें कम दूरी पर बनाया जाता। इसके अतिरिक्त हाईडेंसिटी पद्धति से रोपण ऊंचाई के आधार पर किया जाता है।

कंदूर के आधार पर रोपण - ऊंची-नीची एवं ढाल भूमि में समोच्च (कन्दूर) के आधार पर रोपण किया जाता है।

पौधों की दूरी निर्धारित करना एवं वृक्षों की वृद्धि को ध्यान में रखकर पौध रोपण के लिये गड्डों का खोदना -

यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। भूमि में मिट्टी की गहराई को ध्यान में रखते हुए फल चयन करें तथा उसकी भावी वृद्धि एवं विकास को ध्यान में रखते हुए रोपण के लिए गड्डे वर्गाकार पद्धति से या मिट्टी आकार द्वारा खोदें।

रोपण के लिये पौधों



का चयन

- पौधे जो वानस्पतिक तरीके या टिप्स कल्चर अथवा बीज से तैयार हो उनकी पूरी विश्वसनीयता की जानकारी प्राप्त करके ही लें। उनकी पे डिग्री ज्ञात कर लें। जब तक शासकीय/पंजीकृत रोपणी से ही पौधे लें तथा पौधों पर टैग लगा हो।
- प्रत्येक पौधे को देखें कि उसकी जूटी जिसमें पौधों की जड़ पंकी हो वह सही हो। ग्राफ्ट की जड़े सायन एवं रूट स्टॉक की मोटाई बराबर हो तथा सही तरीके से जुड़ी हों।
- पौधे की बीमारी आदि से ग्रसित न हों। उनकी आयु आदि ज्ञात कर लें।
- जो पौधे चाहे ग्राफ्ट हो, गुटी कलम आदि जैसे भी हो उन्हें भली-भांति परख लें तथा एक सप्ताह तक ब्यारी में उतार कर रखें। जो पौधे सही तरह के स्वस्थ हों उन्हें ही लगायें।
- पौधे लगाते समय पौधा गड्डे के बीज में सीधा लगाया जाये। जड़ को दोनों